साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 23 नवंबर से 29 नवंबर 2026
हम दिखाएंगे आईना...



पेज 02
सीएम साय 26 नवंबर को सुनेंगे लोगों की समस्याएं



पेज 08
PDS फर्जीवाड़ा, परमानेंट बेगुनाह, प्लेसमेंट कर्मी दोषी

वर्ष : 02 अंक : 38 पृष्ठ : 08 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com
पेज 04 एक दशक, जिसने भारत में गरीबी की तस्वीर बदल दी

तीन तूफान, किसान हलाकान

तौल बंद होने से टोकन लेकर लौटे किसान, कटी फसल भीगी



शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में तूफान अकवान की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खरीफ सीजन में यह तीसरा चक्रवाती तूफान है, जिसका असर प्रदेश के अन्नदाताओं पर पड़ रहा है। इससे पहले अर्नब और मुरासु तूफान के कारण भी बारिश और तेज हवाओं से फसलों को नुकसान पहुंचा था। अब पिछले 24 घंटे से रुक-रुककर हो रही बारिश ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में कटी हुई धान की फसल भीग रही है। इससे धान की गुणवत्ता खराब होने और वजन में अंतर आने का खतरा है। वहीं, खेतों में खड़ी फसल के गिरने और पानी भरने की आशंका भी बनी हुई है। रायपुर में धान के नुकसान के बारे में बताते हुए एक किसान इमोशनल हो गए। बारिश का असर धान खरीदी व्यवस्था पर भी पड़ा है। शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में उपार्जन केंद्रों पर तौल रोकनी पड़ी। जिन किसानों ने पहले से टोकन कटवा लिया था, वे किराए के वाहन में धान लेकर केंद्र पहुंचे। लेकिन खरीदी नहीं होने से उन्हें लौटना पड़ा। अब उन्हें नई तारीख और टोकन का इंतजार करना होगा। इससे परिवहन का एक्स्ट्रा खर्च भी उठाना पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में अकवान तूफान को लेकर 20 और 21 नवंबर को अलर्ट जारी किया गया था. 20 नवंबर को अकवान तूफान की वजह से खासतौर पर छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद जैसे जगहों पर अच्छी बारिश हुई है. क्षेत्र के जिन किसानों ने धान काट लिया था, लेकिन उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लगभग 50% धान खराब होने की संभावना है. लेकिन सरकारी आंकड़े आना बाकी है.

कृषि वैज्ञानिक की माने तो धान की खड़ी फसल लगभग 10% प्रभावित हुई है. इसके अलावा सब्जी में भाटा, मिर्च, टमाटर के साथ ही गोभी वर्गीय फसल धूप के बाद बेमौसम बारिश की वजह से कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है. इन फसलों को भी काफी अधिक नुकसान आने वाले समय में होगा. जहां पर जल भराव जैसी स्थिति निर्मित हुई है वहां पर भाटा, मिर्च, टमाटर को नुकसान तो हुआ ही है क्योंकि ये जो सब्जी फसल हैं वो अधिक पानी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है।

छत्तीसगढ़ में इस समय ज्यादातर किसान धान की खेती करते हैं. इस समय प्रदेश के कुछ किसान सोयाबीन की खेती भी करते हैं. लेकिन दीपावली के आसपास उसकी कटाई कर चुके हैं. छत्तीसगढ़ में उतेरा फसल में किसान अर्ली धान लगाते हैं, उसमें तिवड़ा की फसल लेते हैं. ऐसी स्थिति में तिवड़ा को नुकसान नहीं के बराबर होगा. रबी फसल की बात करें तो प्रदेश के किसान चना और गेहूं की फसल लेने वाले हैं. उसके लिए नमी तो आई है लेकिन धान की खाड़ी फसल को बहुत अधिक नुकसान हुआ है.

खरीदे गए धान को बचाना भी चुनौती

बारिश के बीच उपार्जन केंद्रों में पहले से खरीदे गए धान को सुरक्षित रखना चुनौती बन गया है। कई केंद्रों में पानी भरने से तौल का काम प्रभावित हुआ है। धान को कैप कवर और तिरपाल से ढककर रखा जा रहा है। पानी निकासी के लिए नालियां बनाई गई हैं। जमीन की नमी से बचाने के लिए चबूतरे, लकड़ी और भूसे की परत का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं, दुर्ग के कोलिहापुरी केंद्र में खाद गोदाम में धान रखने पर किसान कांग्रेस ने आपत्ति जताई है।

तीन चक्रवाती तूफानों से किसानों का फसल बर्बाद सरकार मुआवजे का आंकलन भी नहीं करवा रही - दीपक बैज



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि पिछले 24 दिनों में तीन चक्रवाती तूफानों के कारण किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। यह तीनों तूफान ऐसे समय आये है, जब किसानों की फसल तैयार हो गयी है। अभी अकवान तूफान के समय बहुत से किसानों का धान खरीदी केन्द्रो पर पहुंच चुका है। वहां पर बे-मौसम बारिश से भीग गया है। बहुत से किसानों का धान बेमौसम बारिश से गिर गया है। लाखो किसानों का धान अभी खेतो में कटकर करपा पड़ा था। बियारा तक नहीं आया है तथा भीग कर वही खराब हो गया है। बस्तर क्षेत्र में पहले ही 1083 गांवो के 74 हजार से अधिक लोग और 6154 हेक्टेयर से ज्यादा फसल प्रभावित हो चुकी है। पूरे प्रदेश में लाखों हेक्टेयर धान की फसल खराब हो चुकी है। लेकिन यह सरकार गंभीर नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले दो तूफानों अर्नव और मुरासू से हुए नुकसान के आंकलन का सर्वे सरकार की तरफ से नहीं करवाया गया है। तीसरे तूफान अकवान का अभी प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। किसानों के नुकसान के आंकलन के लिये कोई प्रयास नहीं किये जाने से सरकार की नीयत में खोट दिख रही है। अब जबकि चक्रवाती तूफान 'अकवान' आया हुआ है, बहुत से किसान धान बेचने के लिये अपना टोकन कटवा चुके थे, लेकिन तीन चार दिनों से खराब मौसम के कारण वे धान नहीं बेच पाये है, उनका टोकन लेप्स हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि तीनो तूफान के समय से ही पटवारी हड़ताल में है। सरकार ने इस हड़ताल को समाप्त करवाने के लिये कोई ठोस प्रयास नहीं किया। पटवारी के माध्यम से ही फसलो के नुकसान का आंकलन करवाया जाता है। पटवारियो के हड़ताल से आंकलन नहीं हो पा रहा। सरकार कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं देख रही। मतलब फसल क्षतिपूर्ति नहीं देना चाहती है। निजी फसल बीमा कंपनिया सरकार के संरक्षण में मोटा मुनाफा कमा रही है, प्रीमियम जमा करके भी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसान इस सरकार की बदनीयती से बर्बाद हो रहे है।

केस-1: रायपुर के केंद्रों में पानी भरा



रायपुर जिले में भी अकवान चक्रवात के असर से पिछले 24 घंटे से रुक-रुककर बारिश होती रही।। इससे धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी प्रभावित हुई है। कई केंद्रों में पानी भरने से तौल का काम रोकना पड़ा। खरीदी के लिए रखे गए धान को कैप कवर से ढककर सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उन किसानों को है, जिन्होंने धान काटकर खेतों में रखा हुआ है। बारिश से धान भीगने पर अंकुरण होने और गुणवत्ता खराब होने का खतरा है। वहीं खेतों में खड़ी फसल पर भी तेज हवा और बारिश का असर पड़ने की आशंका है। किसान श्याम साकरकर और सगु राम साहू का कहना है कि एक तरफ मौसम की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ धान बेचने की चिंता बनी हुई है।

केस-2 : दुर्ग में टोकन के बाद भी नहीं हुई तौल



जिले के कई खरीदी केंद्रों में बारिश के कारण तौल रोकनी पड़ी। शुक्रवार को 1,092 टोकन जारी हुए थे, लेकिन सिर्फ 21 टोकन पर 83.72 मीट्रिक टन धान खरीदा जा सका। अब तक जिले में 2,929 किसानों से 12,356.44 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। गगापुर के किसान मोहन दास मानिकपुरी 300 कट्टा धान लेकर केंद्र पहुंचे थे, लेकिन बारिश के कारण उनकी उपज की तौल नहीं हो सकी। अब उन्हें दोबारा वाहन किराए का खर्च उठाने की चिंता है।

केस-3: धमतरी में सिर्फ 2 केंद्रों पर खरीदी



धमतरी जिले के 108 धान उपार्जन केंद्रों में से आमदी और मगरलोड में ही खरीदी हो सकी। बाकी केंद्रों में बारिश के कारण तौल बंद रही। शंकरदाह सोसायटी में 20 नवंबर के लिए 27 किसानों के टोकन जारी हुए थे, लेकिन खरीदी नहीं हो पाई। केंद्रों में पहले से खरीदे गए धान को तिरपाल से ढककर रखा गया है।

केस-4: बिलासपुर के अधिकांश केंद्रों में तौल प्रभावित



बिलासपुर जिले के 154 खरीदी केंद्रों में से 122 में खरीदी शुरू हो चुकी थी। अब तक 2,856.16 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। शुक्रवार सुबह से लगातार बारिश के कारण अधिकांश केंद्रों में तौल प्रभावित रही। खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान की आशंका है।

केस-5: रायगढ़ में 13 केंद्रों पर ही खरीदी शुरू



रायगढ़ जिले में 112 उपार्जन केंद्रों में से सिर्फ 13 में खरीदी शुरू हो सकी है। यहां 84,501 किसान पंजीकृत हैं। अब तक 232 किसानों से 1,308.72 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। बारिश के कारण शुक्रवार को खरीदी घटकर करीब 200 क्विंटल रह गई।

केस-6: सरगुजा में धान खरीदी हुई बंद



सरगुजा जिले में शुक्रवार को दोपहर बाद बारिश शुरू हुई। मौसम खराब होने और बारिश की आशंका को देखते हुए सभी केंद्रों में दोपहर बाद खरीदी बंद कर दी गई। केंद्रों में पहले से खरीदे गए धान को सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं, बारिश के कारण खेतों में धान की कटाई और मिंजाई का काम भी रुक गया है। मौसम साफ होने के बाद ही खेती-किसानी से जुड़े काम दोबारा गति पकड़ सकेंगे।

ट्रेनें रद्द करने में बिलासपुर सबसे आगे, 9 माह में SECR में 840 रद्द

शहर सत्ता/रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) में जनवरी से सितंबर 2026 तक नौ महीनों में 840 ट्रेनें रद्द हुईं। वहीं, देश के बाकी 7 रेल जोन में भी अलग-अलग कारणों से करीब 2,900 ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं। यानी इन 8 जोन में यात्रियों को ट्रेनों के रद्द होने से बड़े पैमाने पर परेशानी उठानी पड़ी। कहीं तीसरी-चौथी रेल लाइन का निर्माण और नॉन-इंटरलॉकिंग काम वजह बना, तो कहीं मेगा ब्लॉक, भारी बारिश और चक्रवात के कारण ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा। बिलासपुर जोन में रद्द ट्रेनों में 478 मेमू-पैसेंजर सेवाएं थीं, जिन पर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की निर्भरता सबसे ज्यादा है। बरौनी की जगह दरभंगा से चलेगी पूजा स्पेशल- छठ पर्व के बाद घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही गाड़ी संख्या 07562 बरौनी-चर्लपल्ली पूजा स्पेशल के शुरुआती स्टेशन में रेलवे ने बदलाव किया है। 22 नवंबर को चलने वाली यह ट्रेन अब बरौनी के बजाय दरभंगा स्टेशन से रवाना होगी। इस बदलाव का असर बिलासपुर आने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा।

JEE Main 2027 और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों में टकराव!

शहर सत्ता/रायपुर। JEE Main 2027 Session 2 और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों में संभावित टकराव को लेकर विद्यार्थियों की चिंता बढ़ गई है। दोनों परीक्षाएं लगभग एक ही अवधि में आयोजित होने की संभावना है। ऐसे में JEE Main की तैयारी कर रहे 12वीं के विद्यार्थियों के सामने दोनों परीक्षाओं में शामिल होने और उनकी तैयारी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी हो सकती है। विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और CGBSE से परीक्षा कार्यक्रम में समन्वय करने की मांग की है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, JEE Main 2027 Session 2 की परीक्षा 2 अप्रैल से 7 अप्रैल 2027 के बीच आयोजित होने की अवधि बताई जा रही है। वहीं, CGBSE की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च से 8 अप्रैल 2027 तक निर्धारित बताई गई हैं। दोनों परीक्षाओं की तारीखें एक-दूसरे के आसपास होने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल को JEE Main की परीक्षा अवधि के दौरान कुछ विषयों की बोर्ड परीक्षा भी हो सकती है। वहीं, 5 अप्रैल को भौतिकी, 6 अप्रैल को कुछ व्यावसायिक विषयों और 7 अप्रैल को कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षाएं निर्धारित बताई गई हैं। यदि किसी विद्यार्थी की बोर्ड परीक्षा और JEE Main की परीक्षा एक ही दिन पड़ती है, तो उसके सामने किसी एक परीक्षा को चुनने की स्थिति बन सकती है।

जांजगीर-चांपा में बड़ा हादसा: बस की टक्कर से 3 लोगों की मौत

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रहे हादसों में लोगों की जान जा रही है। इसी बीच सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां बस की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस रांग साइड से आ रही थी और उसने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार, तीनों मृतक एक ही गांव दर्री के निवासी थे। उनकी पहचान हरिशंकर चौहान, मोहर दास बैरागी और सेत कुमार पटेल (शिक्षक) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर दर्री से किसी गांव में आयोजित रामसप्ताह कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।

इसी दौरान रास्ते में रांग साइड से आ रही बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे की जानकारी मृतकों के परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं, हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। तीन लोगों की मौत से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि घटना से नाराज लोग चक्काजाम की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चालक की तलाश के साथ ही हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है।

सीएम साय 26 नवंबर को सुनेंगे लोगों की समस्याएं

रायपुर में होगा जनदर्शन, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक करेंगे मुलाकात



शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 26 नवंबर को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन करेंगे। इस दौरान वे प्रदेशभर से आने वाले लोगों से सीधे मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। जनदर्शन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस दौरान लोग अपनी निजी और सार्वजनिक समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रख सकेंगे। मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश देंगे।

पिछला जनदर्शन 8 जनवरी को हुआ था

बता दें कि सीएम का पिछला जनदर्शन 8 जनवरी 2026 को हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करीब 10 महीने बाद फिर जनदर्शन के जरिए आम लोगों से सीधे रूबरू होंगे।

शिकायतों के निराकरण पर रहेगा जोर

जनदर्शन में लोगों को अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखने का मौका मिलेगा। इसमें लोग राजस्व, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास सहित दूसरे विभागों से जुड़ी शिकायतें और मांगें रख सकेंगे। मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारियों को आवेदनों पर कार्रवाई करने और तय समय में समस्याओं का समाधान करने के निर्देश देंगे।



CM का एलान; चक्रवात से फसल खराब हुई तो सरकार देगी मुआवजा

शहर सत्ता/रायपुर। (Chief Minister Vishnu Deo Sai said)छत्तीसगढ़ में चक्रवात अकवान के असर से हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी धान और रबी की फसलों को नुकसान होने की आशंका है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को राहत देने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। नुकसान की पुष्टि होने पर प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6-4 और फसल बीमा के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि चक्रवात के कारण जिन किसानों की फसलों को नुकसान होगा, उनका सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार सहायता राशि दी जाएगी। CM ने कहा कि इससे पहले भी चक्रवात के कारण फसलों को नुकसान हुआ था। उस समय भी सरकार ने सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को सहायता दी थी। इस बार भी नुकसान का आकलन कर किसानों को राहत दी जाएगी।

अन्नदाताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं, CM ने सभी कलेक्टरों को सर्वे के निर्देश

दीपक बैज बोले- धान खरीदी 15 दिन आगे बढ़ाई जाए

शहर सत्ता/रायपुर। बेमौसम बारिश और तीन चक्रवाती तूफानों से फसल को हुए नुकसान के बीच कांग्रेस ने किसानों के लिए 65,100 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। साथ ही धान खरीदी की तारीख 15 दिन आगे बढ़ाने और खराब मौसम के कारण लैप्स हुए टोकन दोबारा जारी करने की मांग उठाई है।

रायपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि, लाखों हेक्टेयर में धान की फसल खराब होने के बावजूद सरकार ने नुकसान का आकलन तक नहीं कराया है। पिछले 24 दिनों में आए तीन चक्रवाती तूफानों ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये तूफान ऐसे समय आए, जब खेतों में धान की फसल तैयार थी। कई किसानों का धान कटकर खेतों में पड़ा था, लेकिन बेमौसम बारिश से भीगकर खराब हो गया। वहीं, खरीदी केंद्रों तक पहुंचा धान भी बारिश की चपेट में आया है।



तूफानों से हुआ नुकसान, किसानों को 65,100 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे सरकार

21 क्विंटल धान और 3100 रुपए के हिसाब से मांगा मुआवजा

दीपक बैज ने कहा कि, कांग्रेस की मांग है कि धान के 21 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को 65,100 रुपए प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति दी जाए। किसानों को हुए नुकसान की तत्काल गणना कर मुआवजा जारी किया जाना चाहिए।

टोकन लैप्स हुए, खरीदी की तारीख 15 दिन बढ़ाने की मांग

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, कई किसानों ने धान बेचने के लिए टोकन कटवा लिया था, लेकिन तीन-चार दिनों तक खराब मौसम के कारण वे खरीदी केंद्र नहीं पहुंच पाए। ऐसे किसानों के टोकन लैप्स हो गए। कांग्रेस ने मांग की है कि, प्रभावित किसानों को दोबारा टोकन जारी किया जाए और मौसम की स्थिति को देखते हुए धान खरीदी की तारीख 15 दिन आगे बढ़ाई जाए।

ललित चंद्राकर बनाए गए BJP ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री

खम्हन ताम्रकार को मिली कार्यसमिति सदस्य की जिम्मेदारी

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ग्रामीण से भाजपा विधायक ललित चंद्राकर को पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं, छत्तीसगढ़ के खम्हन ताम्रकार को ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय ने 21 नवंबर को इन नियुक्तियों की सूची जारी की है। इसमें दोनों नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों और अन्य दायित्वों के लिए नियुक्तियां की गई हैं। जारी आदेश के मुताबिक सभी



नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। इस सूची में देश के अलग-अलग राज्यों के नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ से दो नेताओं को जगह मिली है।

ताम्रध्वज साहू को हराकर बने विधायक

ललित चंद्राकर दुर्ग जिले की दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं। भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें इस सीट से प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता और तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से हुआ।

26 नवंबर संविधान दिवस पर रायपुर में कांग्रेस का मार्च



शहर सत्ता/रायपुर। कांग्रेस 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर रायपुर में संविधान रक्षा मार्च निकालेगी। 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान के तहत होने वाले इस मार्च में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पदाधिकारी और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यात्रा सुबह 11 बजे गांधी मैदान से शुरू होकर अंबेडकर चौक तक जाएगी। इस मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से जारी सूचना में पार्टी पदाधिकारियों, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों, सामाजिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आम लोगों से भी मार्च में शामिल होने की अपील की गई है।

छत्तीसगढ़ में पटवारियों की 40 दिन से जारी हड़ताल स्थगित

CM से मुलाकात के बाद फैसला, कांग्रेस बोली- डरा-धमकाकर आंदोलन खत्म कराया



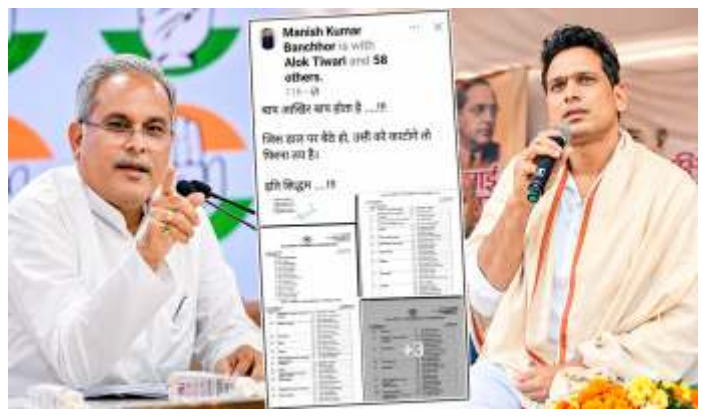
शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की 40 दिन से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद राजस्व पटवारी संघ ने आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया। संघ के प्रांताध्यक्ष ने हड़ताल स्थगित करने संबंधी पत्र भी जारी किया है। पटवारी 13 अक्टूबर से पीवी ऐप की तकनीकी खामियां दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। इससे राजस्व विभाग के कामकाज प्रभावित हो रहे थे। अब पटवारियों के काम पर लौटने से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री श्री साय ने हड़ताल अवधि में हुई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और आपसी समझ के माध्यम से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों और समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील है। छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने तथा उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।

राजस्व के कामकाज पर पड़ा असर

करीब 40 दिनों तक चली हड़ताल से राजस्व विभाग का कामकाज प्रभावित हुआ। जमीन से जुड़े दस्तावेज, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व सेवाओं के काम अटक गए। इसके चलते आम लोगों को अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। वहीं, कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि भाजपा सरकार डराने-धमकाने और नौकरी से निकालने की धमकी देकर दबावपूर्ण तरीके से पटवारियों की हड़ताल खत्म करा रही है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बाप तो बाप होता है से मचा बवाल

शहर सत्ता/रायपुर/भिलाई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक तरफ अपनों के बीच खींचतान है, तो दूसरी तरफ विरोधियों के साथ जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को राष्ट्रीय सचिव पद से हटाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे नेता की एक पोस्ट ने पार्टी में हलचल मचा दी है। बाप तो बाप होता है वाली टिप्पणी ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को गरमा दिया है। वहीं दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा के नाम को लेकर भूपेश बघेल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी आमने-सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं के बीच शुरू हुई बहस अब गांधी परिवार और अडानी तक पहुंच गई है। यानी प्रदेश में कांग्रेस के भीतर भी सियासी खींचतान चल रही है और भाजपा के साथ भी घमासान मचा हुआ है।



देवेंद्र यादव की राष्ट्रीय सचिव पद से छुट्टी, कांग्रेस में हलचल

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नए विवाद की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई सूची से हुई। इस सूची में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया गया है। देवेंद्र यादव की संगठन से विदाई के बाद कांग्रेस के भीतर अलग-अलग चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रह चुके मनीष बंछोर की सोशल मीडिया पोस्ट ने मामले को और गरमा दिया। मनीष ने लिखा, बाप तो बाप होता है... जिस डाल में बैठे हो, उसी को काटोगे तो गिरना तय है... इति सिद्धम। पोस्ट में किसी नेता का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके सामने आने का समय और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इसे देवेंद्र यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के युवा और चर्चित चेहरों में गिना जाता है। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र यादव का राजनीतिक कद बढ़ा था। उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में सचिव की जिम्मेदारी भी मिली थी।



गुरु नानक देव के 557वें प्रकाश पर्व पर निकला नगर-कीर्तन

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में सिख पंथ के पहले गुरु, गुरु नानक देव के 557वें प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन निकाला गया। स्टेशन रोड गुरुद्वारा से शुरू हुआ नगर कीर्तन जेल रोड होते हुए तेलीबांधा गुरुद्वारा पहुंचा। इसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। नगर कीर्तन में बस्तर से आए आदिवासी नृत्य दल की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। इस बार 17 अलग-अलग पालकियों की जगह एक मुख्य पालकी निकाली गई। पूरी संगत एक साथ चलते हुए शबद-कीर्तन करती रही। नगर कीर्तन के रास्ते में जगह-जगह लंगर की व्यवस्था की गई थी। वहीं, पंजाब से आई गतका पार्टी ने पारंपरिक करतब दिखाए। गतका पार्टी ने फायर ब्रीदिंग का प्रदर्शन भी किया। Vइसमें कलाकार ने मुंह से आग की लपटें निकालकर लोगों का ध्यान खींचा। स्टेशन रोड गुरुद्वारा के प्रमुख इंद्रजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि इस बार नगर कीर्तन में केवल एक मुख्य पालकी निकाली गई। इसका उद्देश्य धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के साथ पूरी संगत को एक साथ जोड़ना है।

सोलर पैनल लगाते समय करंट से झुलसा युवक

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में रविवार शाम सोलर पैनल लगाने के दौरान एक युवक 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया। हादसे में 32 वर्षीय शैलेश पारधी बुरी तरह झुलस गया। उसे गंभीर हालत में एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना शाम करीब 4 बजे की है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। यह घटना उरला थाना क्षेत्र की है। उरला थाना प्रभारी सुधांशु बघेल के मुताबिक, चंगोराभाठा के शैलेश पारधी उरला के राजेंद्र नगर में संजय साहू के घर सोलर पैनल लगाने का काम कर रहा था। इसी दौरान छत पर काम करते समय वह पास से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन के संपर्क में आ गया। करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया। हादसे के बाद युवक के दोस्तों और स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल एम्स में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोलर पैनल लगाने के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने का यह पहला मामला नहीं है। करीब पांच महीने पहले पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी में भी ऐसा हादसा हुआ था। उस घटना में प्रमोद चंद्राकर (25) और आशीष चंद्राकर (19) की मौत हो गई थी। तीसरे साथी की शिकायत पर पुलिस ने सोलर पैनल लगाने वाली कंपनी के संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया था।

ठंड की दस्तक तेज! दो दिन बाद 4 डिग्री से ज्यादा लुढ़केगा पारा

शहर सत्ता/रायपुर। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान अकवान के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है, वहीं राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने लगा है। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो रही है। ऐसे में वाहन चालकों को दिन निकलने के बाद भी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को भी प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने के आसार नहीं हैं। इसके बाद तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट आ सकती है। ऐसे में नवंबर के आखिरी दिनों में प्रदेशवासियों को ठंड का ज्यादा एहसास होने लगेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बिलासपुर संभाग के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हुई।

रिंग रोड-2 के 9 किलोमीटर में बनेंगे 7 ओवरब्रिज

हर डेढ़ किलोमीटर पर होगा 1 पुल का निर्माण



शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव की सबसे बड़ी तस्वीर रिंग रोड-2 पर दिखाई दे रही है। बंजारी चौक से टाटीबंध तक करीब 9 किमी के हिस्से में सात ओवरब्रिज बनाने की योजना है। यानी औसतन हर 1.3 किमी पर एक पुल होगा। इनमें तीन का निर्माण जारी है। सोनडोंगरी चौक पर 43 करोड़ रुपए के फोरलेन फ्लाईओवर को मंजूरी मिल गई है। वहीं भनपुरी, व्यास और बंजारी चौक पर तीन नए फ्लाईओवर के लिए सर्वे शुरू हो गया है। इन पर करीब 270 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सातों पुलों की कुल लागत करीब 450 करोड़ रुपए होगी। रिंग रोड-2 औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। यहां भारी वाहनों के साथ कार और दोपहिया वाहनों की आवाजाही बढ़ रही है। प्रमुख चौराहों पर चारों दिशाओं से वाहन पहुंचने के कारण पीक आवर में लंबा जाम लगता है। भारी वाहनों के बीच दोपहिया चालकों को निकलने में परेशानी होती है। इसी दबाव को कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने ओवरब्रिज की योजना बनाई है। पुल बनने के बाद मुख्य मार्ग के वाहन ऊपर से गुजरेंगे, जबकि स्थानीय यातायात नीचे से निकल सकेगा। इससे जाम और हादसों का खतरा कम होने की उम्मीद है। हालांकि, तीन प्रस्तावित फ्लाईओवर की अंतिम लागत और लंबाई डीपीआर बनने के बाद तय होगी।

7 ओवरब्रिज बनने से ये 4 बड़े बदलाव

1. जाम से राहत: मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों को चौराहों पर रुकना नहीं पड़ेगा।

2. स्थानीय ट्रैफिक अलग: सर्विस रोड से कॉलोनियों, बाजारों तक पहुंच आसान होगी।

3. यात्रा का समय बचेगा: वाहनों की कतारें कम होने से समय-ईंधन की बचत।

4. खतरा घटेगा: भारी व हल्के वाहनों के मार्ग को अलग होने से जोखिम कम होगा।

10 महीने में 1111 हादसे,158 लोगों की मौत

राजधानी में जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच 1111 सड़क हादसे हुए। इनमें 158 लोगों की मौत और 667 घायल हुए। यानी औसतन हर महीने 111 और रोजाना तीन से चार दुर्घटनाएं हुईं। बढ़ते ट्रैफिक के बीच ये आंकड़े सड़क सुरक्षा की चुनौती बता रहे हैं। तेज रफ्तार, नियमों की अनदेखी और चौराहों पर वाहनों का दबाव हादसों का जोखिम बढ़ाते हैं। राजधानी में पहले ही करीब 12 प्रमुख ओवरब्रिज राजधानी में टाटीबंध, आमानाका, मोवा, शंकर नगर, कचना-खम्हारडीह, मोहबा बाजार, राजेंद्र नगर, महावीर नगर आर्च ब्रिज, तेलघानी नाका, डीआरएम कार्यालय, भनपुरी और जोरा के प्रमुख ओवरब्रिज शामिल हैं।



सीजीपीएससी को है अध्यक्ष का इंतजार

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) में अध्यक्ष की कुर्सी ढाई महीने से खाली है, लेकिन सरकार अब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकी है। पूर्व अध्यक्ष रीता शांडिल्य के 8 सितंबर को कार्यकाल से मुक्त होने के बाद आयोग की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रभावित होने लगी हैं। राज्य सेवा परीक्षा-2025 के साक्षात्कार से लेकर नई भर्ती परीक्षाओं की तारीख तय करने और अंतिम चयन सूची जारी करने तक कई कामों पर अनिश्चितता का साया है। इसका सीधा असर सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हजारों युवाओं पर पड़ रहा है। परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक विज्ञापन, आवेदन, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने से अभ्यर्थियों की तैयारी का पूरा गणित बिगड़ रहा है। सबसे बड़ा संकट उन युवाओं के सामने है, जिनके पास उम्र सीमा के चलते अब केवल एक-दो प्रयास शेष हैं। भर्ती प्रक्रिया में देरी उनके परीक्षा देने के अवसर तक छीन सकती है। आयोग में अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े मामले भी लंबित बताए जा रहे हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक गलियारों में दो आईएएस अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं, लेकिन फैसला कब होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। नई नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक गलियारों में दो आईएएस अधिकारियों के नामों की चर्चा है। इनमें एक सेवानिवृत्त आईएएस महादेव कावरे अधिकारी हैं, जबकि दूसरे आईएएस अधिकारी सरगुजा संभाग के नरेंद्र दुग्गे बताए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम से नेपाल भी लेगा प्रेरणा



शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्थाओं को अब नेपाल भी समझेगा। राज्य में धान खरीदी से लेकर राशन वितरण तक अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और व्यवस्थाओं का अध्ययन करने नेपाल से 15 सदस्यीय टीम शनिवार को रायपुर पहुंच गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम (वर्ल्ड फूड प्रोग्राम) की पहल पर आई यह टीम 21 और 22 नवंबर को दो दिनों तक खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न केंद्रों और संस्थानों का दौरा करेगी। इस दौरान टीम के सदस्य छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था, राशन एटीएम मशीन और राइस मिलों की कार्यप्रणाली को करीब से समझेंगे। दौरे के दौरान नेपाल की टीम धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करेगी। यहां किसानों से धान खरीदी, पंजीयन, तौल, रिकॉर्ड संधारण और खरीदे गए धान के प्रबंधन की प्रक्रिया समझाई जाएगी। टीम यह भी जानेगी कि धान खरीदी की पूरी व्यवस्था को सुचारु बनाने में तकनीक की क्या भूमिका है और इससे किसानों को किस तरह सुविधाएं मिलती हैं। टीम के अध्ययन का एक प्रमुख हिस्सा राशन एटीएम मशीन भी होगी। इसके जरिए हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, मशीन के संचालन और वितरण व्यवस्था में इसके उपयोग की जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों द्वारा बताया जाएगा कि राशन एटीएम से हितग्राहियों को किस तरह सुविधा मिलती है और राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने में यह तकनीक कैसे मददगार है। साथ ही टीम राइस मिलों का दौरा कर धान की मिलिंग, चावल तैयार करने, गुणवत्ता नियंत्रण और भंडारण से जुड़ी व्यवस्थाओं को समझेगी। खाद्य विभाग के अधिकारी छत्तीसगढ़ में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं के फायदे,साझा करेंगे।

नेपाल में लागू करने की संभावनाओं का होगा अध्ययन

इस दौरे का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपनाए जा रहे तरीकों को समझना है। नेपाल की टीम यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास करेगी कि वहां की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार इन मॉडलों का उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इससे खाद्य सुरक्षा, धान खरीदी और राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा।

बीरगांव चुनाव से 56 बदमाशों को थाने बुलाकर दी समझाइश



शहर सत्ता/रायपुर। बीरगांव नगर निगम चुनाव को देखते हुए रायपुर पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर निगरानी बढ़ा दी है। उत्तर जोन के पांच थाना क्षेत्रों के 56 बदमाशों को थाने बुलाकर समझाइश दी गई। इनमें 39 गुंडा बदमाश और 17 निगरानी बदमाश शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त (उत्तर जोन) दीपमाला कश्यप के निर्देश पर एडीसीपी आदित्य पांडे, एसीपी पूर्णिमा लामा और एसीपी कृष्ण कुमार चंद्राकर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। उरला, खमतराई, गुढ़ियारी, खम्हारडीह और पंडरी थाना क्षेत्रों के बदमाशों को बुलाकर साफ कहा गया कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल न हों। पुलिस के मुताबिक, चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने या अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किस थाने से कितने बदमाश बुलाए गए

खमतराई थाना: 12 गुंडा और 5 निगरानी बदमाश।
गुढ़ियारी थाना: 8 गुंडा और 2 निगरानी बदमाश।
खम्हारडीह थाना: 7 गुंडा और 5 निगरानी बदमाश।
उरला थाना: 6 गुंडा और 4 निगरानी बदमाश।
पंडरी थाना: 6 गुंडा और 1 निगरानी बदमाश।

जशपुर के युवाओं ने हिमालय की 5,340 मीटर ऊंची चोटी पर बनाया 'विष्णु देव रूट'



शररसत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ का जशपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा। जशपुर के पांच आदिवासी युवा अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था से रॉक क्लाइंबिंग गाइड का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण लेंगे। छत्तीसगढ़ के इन पर्वतारोहियों का दिसंबर में बेंगलुरु में प्रशिक्षण होगा। चार युवाओं को लेवल-1 और एक को लेवल-2 प्रमाणन मिलने की उम्मीद है। जशपुर के युवाओं ने हिमालय की 5,340 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी कड़ी में जशपुर जिले के पांच आदिवासी युवाओं का अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था प्रोफेशनल क्लाइंबिंग गाइड्स इंस्टीट्यूट (PCGI) के अंतरराष्ट्रीय रॉक क्लाइंबिंग गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। यह उपलब्धि जशपुर जिले को साहसिक पर्यटन के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रशिक्षण के लिए चयनित युवाओं में तेजल भगत, रुसनाथ भगत, सचिन कुजूर, प्रतीक नायक और रवि सिंह शामिल हैं। इन युवाओं को दिसंबर माह में बेंगलुरु में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में रॉक क्लाइंबिंग की आधुनिक तकनीकों, सुरक्षा मानकों और पेशेवर गाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण भारत के प्रमुख रॉक क्लाइंबिंग आयोजनों में शामिल ROMP के साथ आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चार युवाओं को PCGI लेवल-1 तथा एक युवा को उन्नत लेवल-2 प्रमाणन मिलने की उम्मीद है। इस पहल की सफलता के साथ जशपुर मध्य भारत का पहला ऐसा पर्यटन स्थल बनने की दिशा में अग्रसर है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित रॉक क्लाइंबिंग गाइडों की समर्पित टीम उपलब्ध होगी। इससे जिले में साहसिक पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर विकसित होंगे। जशपुर के इन युवाओं ने वर्ष 2025 में आयोजित ट्राइबल हिमालयन एक्सपीडिशन में अपनी पर्वतारोहण क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस अभियान के दौरान जशपुर की टीम ने हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित 5,340 मीटर ऊंचे जगत्सुख-1 शिखर पर एक नया चढ़ाई मार्ग तैयार करते हुए सफलतापूर्वक आरोहण किया। टीम ने इस नए चढ़ाई मार्ग का नाम मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सम्मान में 'विष्णु देव रूट' रखा। अभियान के दौरान युवाओं ने अल्पाइन शैली में पर्वतारोहण करते हुए साहस, अनुशासन, टीम भावना और तकनीकी कौशल का परिचय दिया। इस अभियान को 15 से अधिक प्रायोजकों का सहयोग प्राप्त हुआ था।

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और लुधियाना के बाद अब रायपुर में होगा ग्लोबल RISE कॉन्फ्रेंस



शररसत्ता/रायपुर। रायपुर। स्वदेशी व्यापारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता आनंद श्रीवास्तव व सह मीडिया प्रभारी शंकर सचदेवा ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और लुधियाना में सफल आयोजन के बाद अब ग्लोबल RISE कॉन्फ्रेंस का आयोजन 25 नवंबर 2026 को रायपुर स्थित होटल बेबीलोन कैपिटल में किया जा रहा है, इस आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लघु उद्योगों, MSME, उद्यमियों एवं व्यापारिक संस्थानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक अवसरों से जोड़ना तथा उनके विकास के नए रास्ते तलाशना है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता श्री अजय भसीन, प्रदेश संयोजक स्वदेशी व्यापारी मंच होंगे। वे अपने उद्बोधन में स्थानीय व्यापार, लघु उद्योगों एवं MSME की भूमिका, उनकी चुनौतियों और वैश्विक बाजार में उनकी संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को बदलते वैश्विक व्यापारिक परिवेश के अनुरूप तैयार होने तथा अपने व्यवसाय को विस्तार देने के विषय में मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम के आयोजक श्री संदीपन रे ने बताया कि "रायपुर का औद्योगिक आधार मजबूत है, लेकिन अब इसके इर्द-गिर्द अधिक मूल्य सृजन करने की आवश्यकता है। तकनीक, मजबूत वैल्यू चेन (मूल्य श्रृंखला) और व्यापक बाजार तक पहुंच व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती है और विकास के नए अवसर खोल सकती है।

रायपुर के उद्योग एवं व्यवसाय इन अवसरों का किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं, इसी महत्वपूर्ण विषय पर SMBConnect | The Global RISE कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी।" ग्लोबल RISE कॉन्फ्रेंस का प्रमुख उद्देश्य छोटे एवं मध्यम उद्यमों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है,

जहां वे उद्योग विशेषज्ञों, निवेशकों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधियों और तकनीकी विशेषज्ञों से जुड़कर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। AI आधारित विकास, वैश्विक व्यापारिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से पैनल डिस्कशन आयोजित होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के उद्योग एवं व्यापार जगत की प्रमुख हस्तियां अपने अनुभव और विचार साझा करेंगी। पैनल डिस्कशन में यूके एवं इटली बिजनेस डेलिगेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योगपति श्री जे.पी. गुप्ता, स्टील उद्योग जगत से श्री महेश बंसल एवं श्री दिनकर बासोटिया शामिल होंगे। इस आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को वैश्विक व्यापार की संभावनाओं से परिचित कराने, उद्योगों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने तथा स्थानीय MSME को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में सार्थक पहल की जाएगी। कार्यक्रम 25 नवम्बर को सुबह 9.30 बजे से प्रारंभ होगा।

संपादकीय



सुकांत राजपूत

कंटेंट की निगरानी पर उठे सवाल

भारत में इंस्टाग्राम की सामग्री सिफारिश प्रणाली में बदलाव की मेटा की घोषणा केवल एक तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि डिजिटल युग की एक महत्त्वपूर्ण चुनौती की ओर संकेत करती है। आज सोशल मीडिया मंच महज संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सूचना, विचार और जनमत को प्रभावित करने वाली शक्तिशाली संस्थाएं बन चुके हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर कौन तय करेगा कि उपयोगकर्ता क्या देखें और क्या नहीं।

मेटा का कहना है कि उन्नत कृत्रिम मेधा की मदद से यौन संकेतों वाली और हिंसक सामग्री की दृश्यता कम की जा रही है। भारत जैसे देश में, जहां करोड़ों युवा और किशोर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, यह पहल स्वागतयोग्य है। लंबे समय से यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि एल्गोरिद्म अक्सर ऐसी सामग्री को बढ़ावा देते हैं जो सनसनी, उत्तेजना व विवाद के जरिए अधिक जुड़ाव पैदा करती है। इससे सामाजिक तनाव, गलत सूचना व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ते हैं। इस पहल का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।दरअसल, कई उपयोगकर्ताओं की शिकायत रही है कि संदर्भविहीन शिकायतों के आधार पर उनकी वैसी सामग्री भी तुरंत हटा दी जाती है, जिनका संदर्भ किसी जरूरी मसले पर असहमति जताने भर से होता है या वह किसी मामले का दूसरा पक्ष होता है। दूसरी ओर, कई बार विवादास्पद सामग्री लंबे समय तक मंच पर रहती है और प्रसार भी पाती है। यह विरोधाभास बताता है कि निगरानी की व्यवस्था त्रुटिरहित नहीं है।

यहीं पारदर्शिता का प्रश्न सामने आता है। यदि किसी सामग्री को सीमित किया जाता है तो उसके मानक स्पष्ट होने चाहिए। साथ ही, उपयोगकर्ताओं को निष्पक्ष अपील और समीक्षा की प्रभावी व्यवस्था भी मिलनी चाहिए। केवल यह दावा करना पर्याप्त नहीं कि शिकायतें घटी हैं, कंपनियों को निर्णयों की प्रक्रिया और मापदंडों को भी सार्वजनिक करना चाहिए।

डिजिटल सुरक्षा आवश्यक है और इससे व्यापक हित सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन स्वस्थ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया मंचों की विश्वसनीयता इसी पर निर्भर करेगी। आखिरकार, समस्या यह नहीं कि लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, यह भी है कि क्या छिपाया जा रहा है और किस आधार पर।

लोगों में अच्छाई को ढूंढिए बुराई तो सब में होती ही है



बुराई में बुराई ढूंढना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि इसकी आदत पड़ जाए तो हम अच्छाई में भी बुराई ढूंढने लगते हैं। यहीं से निगेटिविटी हमारे भीतर उतरने लगती है। बहुत गहराई से अपना मूल्यांकन करना। यदि अपने भीतर आ रही निगेटिविटी के कारण ढूंढने जाएंगे तो एक कारण यह भी निकलेगा कि कहीं हम हर बात में कमजोरी तो नहीं ढूंढ रहे, संदेह तो नहीं कर रहे, प्रतिकूल तो नहीं सोच रहे?

यदि आप दूसरे की अच्छाई देखना चाहें तो विश्वास, सहयोग, सम्मान और भरोसा- यह बचाए रखना। राजनीति की दुनिया में आजकल इन चारों का अभाव है। अटल और आडवाणी ने इन चार बातों का आदर्श स्थापित किया था। एक-दूसरे के प्रति सुलझे हुए संबंध रखे थे। हम भी यह स्वभाव बनाएं। अच्छाई ढूंढिए, बुराई तो सब में होती ही है। रावण जब आखिरी सांस ले रहा था, श्रीराम ने उसको तीर मारा था। लेकिन मरते हुए रावण को देखकर भी राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ इस विद्वान से कुछ सीख लो, क्योंकि इस जैसे लोग धरती पर दोबारा नहीं आते। ऐसी दृष्टि रखिए। पॉजिटिविटी अपने आप भीतर उतर आएगी।

एक दशक, जिसने भारत में गरीबी की तस्वीर बदल दी



श्रीमती निर्मला सीतारामन



एक साल पहले जब मैं नागालैंड की दुर्गम पहाड़ियों में बसे आकांक्षी जिले किफिरे गई थी, तो वहाँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं से संवाद करने का अवसर मिला। उन्हीं में एक 'लखपति दीदी' एस्थर भी थीं। उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि मोटे अनाज से बने उनके उत्पाद अब ऑनलाइन माध्यम से नागालैंड की सीमाओं से निकलकर देश के दूर-दराज के ग्राहकों तक पहुँच रहे हैं। उनके भीतर बेहतर भविष्य का जो आत्मविश्वास था, वह मेरे मन में बस गया। मैंने उनसे कहा कि वे और बड़े सपने देखें और 'करोड़पति दीदी' बनें। उनकी कहानी उस बड़े बदलाव की बानगी थी, जो आज देश के सबसे सुदूर इलाकों तक पहुँच चुकी है - जहाँ भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों ने दशकों तक अवसरों को जकड़ रखा था, लेकिन अब नई उम्मीदें आकार ले रही हैं। पिछले महीने जब विश्व बैंक ने भारत में गरीबी और समानता पर अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की, तो मुझे किफिरे की वह मुलाकात फिर याद आ गई। रिपोर्ट बताती है कि 2011 से 2023 के बीच करीब 50 करोड़ भारतीय गरीबी के चक्र से बाहर निकले हैं और देश में अत्यधिक गरीबी लगभग खत्म हो चुकी है। ये आँकड़े उसी बदलाव की गवाही देते हैं, जिसे मैंने खुद जमीन पर महसूस किया था। एक दौर था जब हालात बिल्कुल उलट थे। आजादी के छह दशक बाद भी बड़े पैमाने पर गरीबी हटाना एक अधूरा सपना ही बना रहा। 2010 के दशक की शुरुआत में भी दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखती थी जहाँ अभाव स्थायी है, जहाँ स्वच्छता, पोषण, स्वच्छ ईंधन और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाएँ आम आदमी की पहुँच से दूर थीं। तब यही मान लिया गया था कि गरीबों के हाथ में कुछ नकद थमा देने से गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। बीते एक दशक ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने तात्कालिक राहत के बजाय उन जड़ों पर प्रहार किया है, जो गरीबी को बार-बार जन्म देती हैं। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण यानी 'अंत्योदय' के मंत्र को अपनाते हुए हमारी सरकार ने कठिन लेकिन स्थायी रास्ता चुना, हर परिवार की जरूरतों को समझा और यह सुनिश्चित किया कि विकास का लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद तक पहुँचे।

सटीक लक्ष्य, ठोस परिणाम

गरीबी का अर्थ सिर्फ कम आमदनी नहीं है। यदि किसी परिवार के पास पक्की छत, साफ पानी, शौचालय या इलाज की सुविधा न हो, तो कमाई बढ़ने के बाद भी वह असुरक्षित ही रहता है। एक गंभीर बीमारी उसकी वर्षों की जमा-पूँजी छीनकर उसे फिर से गरीबी के गर्त में धकेल सकती है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने हर योजना को जरूरतमंदों की वास्तविक समस्या के अनुरूप गढ़ा और उसके ठोस परिणामों पर जोर दिया। यह बदलाव किसी जादू से नहीं आया। इसके लिए लाभार्थियों की सही पहचान, जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और आखिरी घर तक लाभ पहुँचने की निरंतर निगरानी जरूरी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं हर योजना की बारीकी से समीक्षा की, जहाँ अड़चनें आईं उन्हें दूर किया और पारदर्शिता के लिए तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। इसी निरंतरता ने सरकारी नीतियों को आम लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव का माध्यम बना दिया।

घर से शुरू हुई सेहत और सम्मान की राह

कोई भी परिवार तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक बीमारी और रोजाना पानी ढोने की मशक्कत उसकी ऊर्जा और संसाधन निगलती रहे। 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत घर-घर शौचालय बनने से न केवल सम्मान मिला, बल्कि एक अनुमान के अनुसार हर साल 60 से 70 हजार शिशुओं की अकाल मृत्यु रोकने में मदद मिली। 'जल जीवन मिशन' के जरिए ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन 2019 के करीब 3 करोड़ से बढ़कर आज लगभग 16 करोड़ तक पहुँच गए हैं। इससे महिलाओं और बेटियों को पानी के लिए मीलों पैदल चलने से मुक्ति मिली और जलजनित बीमारियों का खतरा भी घटा। इसी तरह 'उज्ज्वला योजना' ने रसोई को धुएँ से आजाद किया, तो 'पीएम आवास योजना' ने पक्के घर की सुरक्षा और गरिमा दी। वहीं,'आयुष्मान भारत' के तहत कैशलेस इलाज ने बीमारी के भारी-भरकम खर्च से परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। इन योजनाओं ने मिलकर एक ऐसे सुरक्षा चक्र का काम किया है, जिसने घरेलू खर्च घटाया, काम के लिए समय बचाया और परिवारों को दोबारा गरीबी में फिसलने से रोका।

बैंक खाते से उद्यमिता की उड़ान

सामाजिक सुरक्षा परिवारों को संबल देती है, लेकिन आर्थिक रूप से ऊपर उठने के लिए आजीविका के अवसर जरूरी हैं। करोड़ों भारतीयों के लिए इस नई शुरुआत की पहली सीढ़ी एक बैंक खाता बना। कभी यह कड़वा सच माना जाता था कि सरकारी खजाने से निकले एक रुपये में से सिर्फ पंद्रह पैसे ही आम आदमी तक पहुँचते हैं। 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' ने इस व्यवस्था को इतिहास बना दिया। आज 59 करोड़ से अधिक 'जन धन' खातों के जरिए सरकारी मदद बिना किसी बिचौलिए के सीधे हकदार के खाते में पहुँच रही है। तकनीक ने इसे अभूतपूर्व पैमाने पर संभव कर दिखाया। बैंक खाते ने लोगों को सुरक्षित बचत की आदत दी और उनका वित्तीय रिकॉर्ड तैयार किया, जिससे संस्थागत कर्ज के रास्ते खुले। जिनके पास गिरवी रखने को कोई संपत्ति नहीं थी, उनके लिए यह पहला कर्ज जीवन बदलने वाला साबित हुआ। दो महीने पहले मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान मेरी भेंट पश्चिम बंगाल की सुष्मिता घराई से हुई। कोरोना महामारी में पिता को खोने के बाद उनके परिवार का प्रिंटिंग व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया था। न जमीन थी, न सोना, लेकिन बिना गारंटी वाले मुद्रा ऋण ने उन्हें अपना प्रेस दोबारा खड़ा करने की ताकत दी। आज वे आठ लोगों को रोजगार दे रही हैं, जो उनकी शुरुआती टीम से दोगुना है, और अब डिजिटल प्रिंटिंग में विस्तार की तैयारी कर रही हैं। उनका जज्बा उन करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिनके हौसले उनके संसाधनों से कहीं बड़े हैं। अब तक मुद्रा योजना के तहत 60 करोड़ ऋण खाते स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें करीब दो-तिहाई महिलाओं के हैं। इसके साथ ही 'पीएम स्वनिधि' और 'पीएम विश्वकर्मा' जैसी योजनाएँ रेहड़ी-पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई पहचान और आर्थिक मजबूती दे रही हैं। इस पूरे आर्थिक बदलाव की धुरी देश की महिलाएँ रही हैं। आज 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जो DAY-NRLM और अन्य पहलों के जरिए बचत, कौशल और उद्यमिता के मजबूत मंच बन गए हैं। 3.7 करोड़ से अधिक महिलाएँ 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं और कई अब 'करोड़पति दीदी' बनने की राह पर हैं। वहीं, 'नमो ड्रोन दीदी' के रूप में प्रशिक्षित महिलाएँ आज खेतों में ड्रोन से छिड़काव की आधुनिक सेवाएँ दे रही हैं। जो महिलाएँ कभी आर्थिक मुख्यधारा से बाहर थीं, वे आज खुद रोजगार देने वाली उद्यमी बन रही हैं।

विकसित भारत का संकल्प

पीढ़ियों तक यह मान लिया गया था कि भारत में गरीबी को केवल संभाला जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। एक दशक पहले जो असंभव लगता था, वह वर्षों के निरंतर और सार्थक जमीनी प्रयासों से आज हकीकत बन चुका है। लेकिन यह ठहरने का समय नहीं है। 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की अपनी नई चुनौतियाँ हैं। अगले चरण में हमें विकास की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर बचे लोगों को भी गरीबी से बाहर निकालना है और यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनकी प्रगति निर्बाध जारी रहे। सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ अब वित्त, बाजार और डिजिटल अर्थव्यवस्था तक आम लोगों की पहुँच को और व्यापक बनाना होगा। सरकार रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के जरिए शिक्षा और उद्योग के बीच मजबूत सेतु बना रही है, जबकि आधुनिक बुनियादी ढाँचे में निवेश देश को अभूतपूर्व गति से जोड़ रहा है। अब विकास के अवसर केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं रह सकते।

प्रधानमंत्री का कहना है कि आजादी की तरह ही 'विकसित भारत' भी एक ऐसा संकल्प है, जिसे हर देशवासी को जीना होगा। जो लक्ष्य छह दशकों तक अधूरा रहा, उसे दस वर्षों में साकार करने के बाद भारत अगले दो दशकों की ओर पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ा रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति और संकल्प से 2047 तक विकसित भारत का सपना हमारी पहुँच में है - और हम सब मिलकर इसे अवश्य पूरा करेंगे।

(लेखिका भारत सरकार में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं)

नव वामपंथियों के निशाने पर लोकतंत्र

अवधेश कुमार



नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गत दिनों अमेरिका में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव प्रणाली और अर्थव्यवस्था आदि पर जो टिप्पणियां कीं, वे उनकी भावी राजनीतिक दिशा का संकेत देती हैं। हाल में हैदराबाद में भारत समिट-2026 आयोजित कर उन्होंने इसे वैश्विक अभियान का रूप देने का प्रयास किया। समिट की थीम थी-एक नए विश्व का निर्माण। कांग्रेस ने इसे वैश्विक न्याय, लोकतंत्र, बहुपक्षवाद, मतदाताओं के अधिकार और नफरत की राजनीति के खिलाफ वैकल्पिक विचारों का मंच बताया। इससे उसका वास्तविक उद्देश्य समझना कठिन नहीं है।

इसी समिट के मंच से इटली की पार्टी आफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने जिस अंदाज में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा दिया, वह राहुल गांधी की शैली जैसा ही था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए वे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। आखिर इस समर्थन का मतलब क्या है? यह किसी विदेशी का विपक्ष के माध्यम से भारत के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। राहुल गांधी ने सामने बैठे हुए जिस तरह मुस्कुराकर ताली बजाई, उससे लगता है कि वे अब इसी रास्ते पर चलने वाले हैं।

आज पूरी दुनिया में एक अजीब किस्म के नव वामपंथी उभरे हैं। ये खुद को उदारवादी और वैकल्पिक विचारों का प्रतिनिधि बताते हैं। कुछ देशों की सरकारों में भी इनकी मौजूदगी है। यूरोप से लेकर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तक कट्टर इस्लामवादी भी इनके साथ दिखाई दे रहे हैं और अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की शुरुआत 2017 से कराई गई। इन लोगों से उनका संपर्क और संबंध बना और तब से उनकी भाषा और व्यवहार में बदलाव साफ दिखाई देता है। वे विदेश में भारत विरोधियों से मिलने में न हिचकते हैं और न ही लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार आदि के नाम पर अपने देश की निंदा करने से। यह एक ऐसी चुनौती है, जिससे निपटने के रास्ते तलाशने होंगे। इन नव वामपंथियों के निशाने पर केवल अपने देश के राष्ट्रवादी ही नहीं, बल्कि वे नेता और देश भी हैं, जो अपनी सभ्यता, संस्कृति और क्षमता के बल पर श्रेष्ठ स्थान बनाने का माद्दा रखते हैं और अपने लोगों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। लगता है कि कांग्रेस में इसी श्रेणी के रणनीतिकारों ने राहुल गांधी को भारत में ऐसा सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि देश के साथ-साथ विदेश में भी उनके संपर्क, सम्मान और अभियान को व्यापक समर्थन प्राप्त है। आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम और अभियान और भी देखने को मिल सकते हैं।

हालांकि भारत समिट के लिए कांग्रेस को देश-दुनिया में वैसा समर्थन नहीं मिला, जैसी तैयारी की गई थी। विजन के नाम पर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उसमें वैश्विक दृष्टि की गंभीर झलक नहीं थी। वस्तुतः मोदी सरकार को फासीवादी सरकार के रूप में प्रचारित करने के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने समिट में कहा, "फासीवादी लोगों की आवाज तेज होती है। पिछले एक दशक से फासीवादी लोग चिल्ला रहे हैं और अधिकांश जनता देख रही है कि हो क्या रहा है। 2014 के चुनाव में पहली बार देखा कि करोड़ों डालर खर्च हो रहे हैं। यह देख हम हैरान थे।" यहां राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि उस समय तो केंद्र में उनकी सरकार थी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी उनके शासनकाल में होती थी, फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने आगे कहा, "मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हम मोदी को हराने जा रहे हैं।" उन्हें मोदी और अमित शाह की आंखों में डर दिखाई दे रहा है और वह भी हार का! वास्तव में वे इस तरह देश और विदेश में लोगों के भीतर यह भाव पैदा करना चाहते हैं कि तीन बार हारने के बाद अब वे जीतकर सरकार में आने वाले हैं। उथल-पुथल पैदा करने से लेकर चुनावों तक, इस तरह के माहौल का सामूहिक मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। यही उनकी रणनीति है।

दरअसल राहुल गांधी और उनके देसी-विदेशी रणनीतिकारों का लक्ष्य और दिशा स्पष्ट है। देश के भीतर और दुनिया भर में लगातार बोलो और बुलवाओ, ताकि यह माहौल बने कि भारत में एक व्यक्ति, एक वोट के आधार पर सरकार नहीं बन रही, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और चुनाव आयोग हर हाल में भाजपा की सरकार को वापस लाने के लिए काम कर रहा है। यह नव वामपंथियों की ऐसी शैली है, जिसमें पहले की तरह हिंसक क्रांति और हथियारों के बल पर सत्ता पर कब्जा नहीं किया जाता, बल्कि हिंसक अराजकता और उथल-पुथल का माहौल बनाया जाता है, ताकि जनता की चुनी हुई सरकार कमजोर पड़े और सत्ता परिवर्तन का रास्ता बने। अनेक देशों में ऐसे हिंसक आंदोलन होते और सत्ता बदलती दिखाई दे रही है। इसलिए यह चिंताजनक स्थिति है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और कई राज्यों में उनके दल की सरकारें हैं। ऐसे में उनके पास राजनीतिक और संवैधानिक शक्ति भी है। इससे चुनौती और बढ़ जाती है। भारत विरोधी शक्तियां इस परिस्थिति का लाभ उठाकर क्या करेंगी और किस सीमा तक जा सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना कठिन है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)



FBI ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को मोस्ट वांटेट किया घोषित

नई दिल्ली। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) ने गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को अपनी 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में शामिल किया है. एफबीआई के अनुसार, गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध गिरोह (ओसीजी) का उत्तरी अमेरिका में कथित प्रमुख है. इस गिरोह पर अमेरिका और कनाडा में कई तरह के हिंसक अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं. एफबीआई के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध गिरोह पर राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों की हत्या, गोलीबारी, हत्या, अपहरण, फिरौती वसूली और हमले जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप है. इसके अलावा गिरोह पर मानव तस्करी और मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी में संलिप्त होने के भी आरोप लगाए गए हैं.एफबीआई ने गोल्डी बराड़ को ऐसे आपराधिक नेटवर्क का कथित उत्तरी अमेरिकी नेता बताया है, जिसकी गतिविधियां अमेरिका और कनाडा तक फैली हुई हैं. एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किए जाने के बाद उसकी तलाश को लेकर अमेरिकी जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी.गौरतलब है कि गोल्डी बराड़ का नाम भारत में भी कई आपराधिक मामलों में सामने आता रहा है. हालांकि, एफबीआई की ओर से जारी जानकारी में उस पर लगाए गए आरोपों को कथित अपराधों के रूप में ही बताया गया है.

आतंकवाद का समाधान सामूहिक रूप से निकले

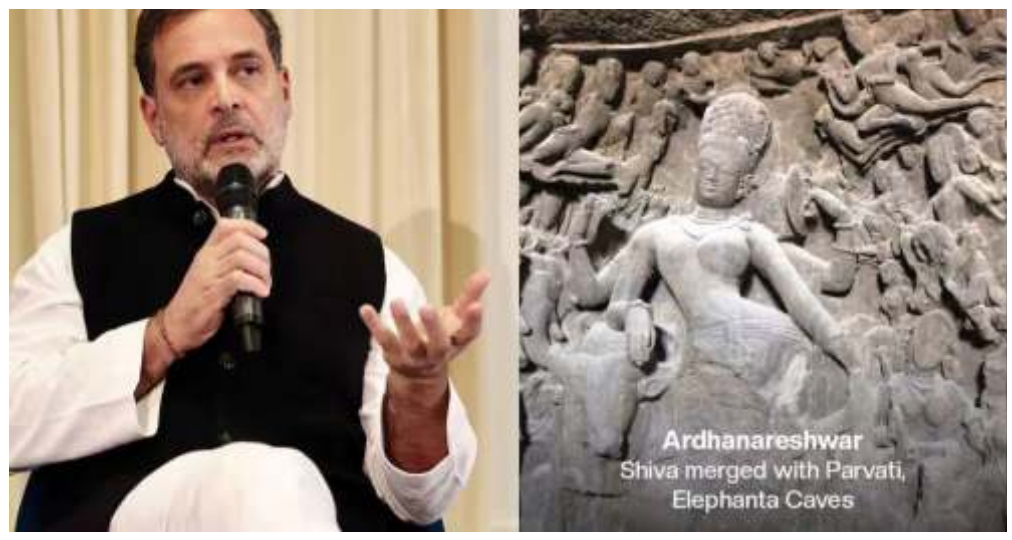
नई दिल्ली। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यतागत संवाद मंच में शामिल होने आए पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने आतंकवाद के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस विषय पर किसी भी तरह की चर्चा ठोस सबूतों के आधार पर होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरा क्षेत्र आतंकवाद की चपेट में है, इसलिए इसका समाधान भी सामूहिक रूप से मिलकर निकाला जाना चाहिए. मीडिया से बातचीत के दौरान मुसादिक मसूद मलिक ने कहा, 'मैंने कल भी कहा कि जब भी इस पर बात होगी तो सबूतों के आधार पर होगी. मुझे लगता है कि पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में है. मैं इस पर बात करने नहीं आया हूं. हमारे यहां तो हजारों लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं. रोज हमारे यहां लोगों की जान जा रही है. इसका हल केवल एक ही है कि हम तमाम सबूत एकदूसरे के सामने लेकर के आएं.'

कनाडा में भारतीय मूल के दो लोगों की हत्या

नई दिल्ली। कनाडा में दो भारतीय मूल के लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई है. यह घटना 15 नवंबर की रात कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में वॉलमार्ट के एक स्टोर के बाहर हुई. पुलिस का मानना है कि इस हत्याकांड को निशाना बनाकर अंजाम दिया गया और इसका संबंध संगठित अपराध से हो सकता है. पुलिस ने मृतकों की पहचान 23 वर्षीय गगनप्रीत (गैरी) रेहल और 24 वर्षीय सुखजीत कौर के रूप में की है. दोनों 15 नवंबर की रात वॉलमार्ट स्टोर के बाहर हुई गोलीबारी में घायल हो गए थे और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि दोनों मृतक पड़ोसी डेल्टा टाउनशिप में रहते थे. रेहल हथियारों से जुड़े अपराधों के मामलों में पुलिस के रिकॉर्ड में था, जबकि कौर के कनाडा में परिचित लोगों की संख्या गिनी-चुनी थी. CBC न्यूज ने सार्जेंट फ्रेडा फोंग के हवाले से बताया कि पुलिस का मानना है कि रात 10 बजकर 51 मिनट पर घटनास्थल के पास एक कार में लगी आग का गोलीबारी से संबंध है।

'सनातन को डेंगू-मलेरिया बताया', राहुल के बयान पर बवाल

अर्धनारीश्वर' पोस्ट पर भड़की बीजेपी



नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 'अर्धनारीश्वर' पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने करारा पलटवार किया है. भाजपा ने राहुल गांधी पर सनातन धर्म के प्रति जन्मजात नफरत रखने का आरोप लगाया है. भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से जोड़ने वाले बयान का हवाला दिया, वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया. प्रदीप भंडारी ने कहा कि भारत को राहुल गांधी के व्याख्यान की कोई जरूरत नहीं है, जो हिंदू धर्म को हिंसा से जोड़कर देखते हैं और वोट बैंक की राजनीति के कारण पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं.

राहुल को बीजेपी ने घेरा

उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "जितना मैंने राहुल गांधी को सुना, उतना ही मुझे यह एहसास हुआ कि उन्हें सनातन धर्म से जन्मजात नफरत है. उन्होंने सनातन को डेंगू-मलेरिया कहा, जिसे भुलाया नहीं जा सकता."वहीं, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक की विरोधी है और इसे लागू होने से रोकती है. कंगना ने सवाल किया कि अगर भाजपा की सोच पुरुषवादी है, तो वह महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए क्यों प्रयास करती है?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वह पार्टी है, जो इस विधेयक का विरोध कर रही है.गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर बड़ा हमला बोला था. उन्होंने भाजपा-आरएसएस को 'असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुषवादी मानसिकता वाला' बताते हुए कहा था कि उन्हें भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की कोई समझ नहीं है.

राहुल ने क्या कहा था?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए निशाना साधा था. उन्होंने एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित 'अर्धनारीश्वर' मूर्ति की तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती को एक ही रूप में दर्शाया गया है.उनकी यह पोस्ट उस विवाद के बाद आई थी, जो सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन के मौके पर अपने माता-पिता (सोनिया और राजीव गांधी) के रिश्ते पर की गई उनकी टिप्पणी के बाद खड़ा हुआ था.इससे पहले, राहुल गांधी ने 17 नवंबर को भी एक पोस्ट साझा की थी. इसमें उन्होंने 12वीं सदी के एक मंदिर की मूर्ति की तस्वीर साझा की थी, जिसमें देवी पार्वती को भगवान शिव की गोद में बैठे हुए दिखाया गया है. उस पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा था कि डर, गुस्से और नफरत ने भाजपा और आरएसएस समर्थकों के दिलों में ऐसा जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्रेम जाहिर करने से रोकता है. उन्होंने आगे लिखा था, "एक सच्चे हिंदू के रूप में, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से आजाद करूं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनेपन की अद्भुत सुंदरता और आनंद का अनुभव कर सकें. सत्यम शिवम सुंदरम."

सनातन को लेकर कोई शंका नहीं : मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 20 साल पहले का समय कैसा था? हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि आगे क्या होगा, क्या यह टिक पाएगा या नहीं. क्या इसका अस्तित्व बचेगा या नहीं. हालांकि, इतनी कड़ी मेहनत और प्रयासों की बदौलत, आज सनातन धर्म के उत्थान को लेकर किसी भी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है. उत्तराखंड के हरिद्वार में शनिवार (21 नवंबर 2026) को अखिल विश्व गायत्री परिवार की संस्थापिका भगवती देवी शर्मा के जन्मशताब्दी समारोह था. इस समारोह में RSS प्रमुख मोहन भागवत को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था. उन्होंने कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म का जिक्र किया. मोहन भागवत ने आगे कहा कि यह अब किस्मत में लिखा जा चुका है. ऐसा होकर ही रहेगा. हालात को देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है. लोग कहते हैं कि जब इंसान हालात को देखता है तो वह डर जाता है, लेकिन यह सच नहीं है. ऐसा नहीं होता. जब मन में डर होता है, तभी हालात भयानक लगते हैं. अगर मन में संकल्प और उत्साह हो, तो इंसान को हालात से डर नहीं लगता. डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि भागवान के कामों के संचालन के लिए भगवान स्वयं नहीं आते, बल्कि योग्य व्यक्तियों एवं संगठनों को इसका दायित्व सौंपते हैं. सनातन संस्कृति पर बढ़ते भरोसे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है।

यूपी चुनावः सहयोगियों को 55 से 60 सीट देगी भाजपा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होते ही राज्य की सियासत में हलचल बढ़ गई है। आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सियासी गलियारों और पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, बीजेपी इस बार विधानसभा की कुल 403 सीटों में से अपने सहयोगी दलों के लिए लगभग 55 से 60 सीटें छोड़ सकती है। वहीं, खुद बीजेपी 340 से 350 विधानसभा सीटों पर अपने चुनाव चिह्न 'कमल' के साथ मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है। हालांकि, सीटों के इस संभावित फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लगना इतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से काफी बदलाव आ चुका है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 376 सीटों पर



अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था। उस समय यूपी में बीजेपी का गठबंधन केवल दो क्षेत्रीय दलों—अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले 'अपना दल (सोनेलाल)' और डॉ. संजय निषाद की 'निषाद पार्टी' के साथ था। लेकिन 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एनडीए का कुनबा बढ़ चुका है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुल 4 प्रमुख क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में है। पुराने सहयोगी अपना दल (एस) और निषाद पार्टी के अलावा अब पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ रखने वाली जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) और पूर्वांचल में प्रभाव रखने वाली ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) भी एनडीए का हिस्सा हैं। बढ़े हुए सहयोगियों को साधने की बड़ी चुनौतीचूंकि 2022 के मुकाबले 2027 में बीजेपी के दो सहयोगी दल (आरएलडी और सुभासपा) बढ़ गए हैं, इसलिए पार्टी को अपने कोटे की सीटों में कटौती करनी पड़ रही है। जहां पिछली बार बीजेपी 376 सीटों पर लड़ी थी, वहीं इस बार उसे 340 से 350 सीटों के दायरे में सिमटना पड़ सकता है।

बांग्लादेश में 200 हिंदू परिवारों के घरों को आग लगाने का दावा

नई दिल्ली। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थक हंगामा कर रहे हैं. बता दें कि तारिक रहमान की मौजूदा सरकार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) आवामी लीग पर हिंसा फैलाने की आरोप लगा रही है. दूसरी तरफ से बांग्लादेश अवामी लीग छात्र संगठन के अध्यक्ष अल अमीन रहमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया है कि आवामी लीग के समर्थक समेत 200 हिंदुओं घर को निशाना बनाया गया है और आग लगा दिया गया है. बांग्लादेश में आगजनी की घटना के लिए आवामी लीग ने BNP और जमात समर्थकों को जिम्मेदार माना है. उन्होंने मानवाधिकार संगठनों से जांच की मांग की है. इस तरह से बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा के आग में जल रहा है. बीते कई दिनों से बैन की गई पार्टी आवामी लीग और BNP के बीच टकराव जारी है. इस वजह से देश में हिंसा का माहौल बना हुआ है. हसीना ने दिसंबर 2026 में भारत से बांग्लादेश लौटने की योजना की घोषणा की थी. सरकार ने उनके नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के अनुरोध को खारिज कर दिया. इसके बाद आवामी लीग के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।

मैं खुश हूं लोगों ने सोना कम खरीदाः पीएम मोदी

नई दिल्ली। सोना-चांदी की कीमतों में इन दिनों गिरावट का दौर जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (21 नवंबर) को इस बात पर खुशी जताई कि पिछले साल उनकी अपील के बाद लोगों ने सोना कम खरीदा है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से सोने की कीमतों में गिरावट आई. लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज आपने देखा होगा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इस चर्चा में हर कोई कह रहा है कि मोदी जी ने 2023 में संसद में कहा था कि आपको अपना पैसा भारत सरकार के PSU (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) द्वारा जारी किए गए बॉन्ड में निवेश करना चाहिए.



सोने की कीमतों में गिरावट पर क्या कहा

पीएम मोदी ने कहा कि इससे आप बहुत पैसा कमाएंगे. उस समय लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने निवेश किया, उन्होंने खूब पैसा कमाया. सोने की कीमतों में आई गिरावट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "एक साल पहले, मैंने अपने देशवासियों से अपील की थी कि अगर आपको जरूरत न हो, तो कृपया एक साल तक सोना न खरीदें. मुझे खुशी है कि मेरे जैसे एक आम इंसान की बात मानकर लोगों ने सोना कम खरीदा, जिससे सोने की कीमतें गिर गईं."

हुनर-प्रतिभा की डिमांड बढ़ेगी- पीएम मोदी

उन्होंने आगे कहा, "आज मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं. मेरी बात ध्यान से सुनें, समय बदल रहा है. अब केवल कागजी सर्टिफिकेट लेकर, सूट-टाई पहनकर घूमने वालों के बजाय, हुनरमंद लोगों की ज्यादा कद्र होगी जिनके पास हुनर और प्रतिभा है, उनकी मांग बढ़ेगी." प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "मुझे खुशी है कि जिस तरह एक समय देश के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर लोगों ने एक वक्त का भोजन छोड़ दिया था, उसी तरह हमारे देशवासियों ने मेरी बात सुनी. हमारे देश का चरित्र ही ऐसा है."

सीमा विवाद से नए प्रोजेक्ट्स पर होगी चर्चा

खास है नेपाल के पीएम बालेन शाह का भारत दौरा

नई दिल्ली। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह दो दिन की यात्रा की भारत पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका यह पहला विदेशी दौरा है. उनकी इस यात्रा को भारत-नेपाल संबंधों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है. बालेन शाह की पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे. भारत और नेपाल के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत संभावित है, जो लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव का केंद्र बने हुए हैं. बालेन शाह के भारत दौरे को लेकर भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने कहा, 'यह नेपाल प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा और भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है. इससे नेपाल-भारत संबंधों के लिए एक नई और भविष्य की ओर देखने वाली नींव रखने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, कुछ राजनीतिक मुद्दे जैसे, सीमा विवाद और 1950 की संधि का मुद्दे पर भी नजर रहेगी, जिनको पिछली सरकारें अलग-अलग मंच पर उठाती रही हैं.



क्या बोले पूर्व राजदूत?

उन्होंने आगे कहा, 'नए हवाई प्रवेश मार्ग के क्षेत्र में अभी भी बातचीत चल रही है, जो नेपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा. शर्मा ने कहा मुझे लगता है कि नेपाल भारत से कई कामों के लिए किसी तरह के कर्ज और आर्थिक मदद की उम्मीद कर रहा है, जिसमें बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें, नेपाल में अन्य निर्माण कार्य और अब भोटेकोशी आपदा के चलते विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास का काम शामिल है.नेपाल के पूर्व राजदूत ने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर कई आर्थिक सहयोग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे, जिसमें भैरहवा एकीकृत जांच चौकी (इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट), लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना, पुलिस अकादमी आदि शामिल हैं.'

राष्ट्रपति मुर्मू से करेंगे भेंट

इस साल 5 मार्च को नेपाल में हुए चुनावों के बाद 27 मार्च को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से बालेन शाह की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है. अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शाह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट करेंगे. वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे.

भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंध मजबूत होने की उम्मीद

विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा से दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने और सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है. इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आपसी मानवीय संबंध रहे हैं.

'गोवा बिल्डरों का नहीं, यहां के लोगों का', अभिजीत दीपके ने BJP सरकार को घेरा

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अभिजीत दीपके ने शनिवार (21 नवंबर 2026) को गोवा की सरकार पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उत्तरी गोवा जिले के करापुर-सरवन गांव में एक निजी कंपनी की मेगा हाउसिंग परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों पर बेरहमी से हमला किया गया. इसके बावजूद राज्य सरकार को सिर्फ बिल्डरों की परवाह है. करापुर-सरवन में गुरुवार (19 नवंबर 2026) की रात हुई झड़प में कम से कम 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है. मायेम विधानसभा क्षेत्र में स्थित इस गांव का दौरा करते हुए, दीपके ने दावा किया कि गंभीर रूप से घायल गौरीश घडी को विशेष रूप से इस परियोजना का विरोध करने के कारण निशाना बनाया गया था. अभिजीत दीपके रविवार (21 नवंबर 2026) को गोवा से पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान क्या बोलती पब्लिक की शुरुआत करने के लिए वहां पहुंचे हैं. दीपके ने बताया कि घडी पर कथित तौर पर दरांती से हमला किया गया, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और सिर पर चोटें आईं. CJP नेता ने सवाल किया, "क्या उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने गांव और वहां के लोगों की जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे थे?"



युजवेंद्र चहल के BJP ज्वाइन करने पर पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने दी बधाई

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने राजनीति में कदम रख दिया है. शनिवार को उन्होंने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है. चहल, BJP के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं. चहल के राजनीति में प्रवेश करने पर पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन की प्रतिक्रिया सामने आई है. तेज गेंदबाज अतुल वासन 1990-1991 के समय में भारत के लिए 13 इंटरनेशनल मैच खेले थे. उन्होंने युजवेंद्र चहल के राजनीति में आने और लोकसेवा में योगदान की इच्छा की सराहना की. अतुल ने चहल को बधाई दी और जनसेवा में काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की बात भी कही. भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले युजवेंद्र चहल ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य से मिले थे. उसके बाद उनका नाम कार्कारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया. बताते चलें कि चहल कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले और अब उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में इंटरनेश्नल डेब्यू की उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि वह फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अतुल वासन ने कहा, "जब कोई खिलाडी नाम कमाता है और उसकी लोकसेवा में रूचि होती है. साथ ही उसमें योगदान देने का पक्का इरादा और सच्ची चाहत भी होती है. मैं उन्हें बधाई देता हूं.

अंबानी परिवार ने दान किए 620 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। देश के बड़े उद्योगपतियों की कमाई और उनकी संपत्ति की चर्चा होती है. ऐसे में देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनका परिवार केवल कारोबार के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक कामों में योगदान के मामले में भी लगातार चर्चा में बना रहता है.हाल ही में जारी हुई हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में मुकेश अंबानी और उनके परिवार का नाम शामिल है. इस साल उन्होंने 620 करोड़ रुपये दान किए हैं. हालांकि, पिछले साल के मुकाबले में दान थोड़ा कम हुआ, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने देश के टॉप 5 दानदाताओं की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में मुकेश अंबनी और उनका परिवार किस नंबर पर है? बता दें कि पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने 626 करोड़ रुपये दान किए थे. वहीं इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 620 करोड़ रुपये दान किए हैं. यानी उनके योगदान में लगभग 1 प्रतिशत की कमी आई है.

रुपया 8 साल में मजबूत, सेंसेक्स 9 महीने के टॉप पर

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए नवंबर का महीना अच्छी खबरें लेकर आया है. एक तरफ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार मजबूत हो रहा है, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार में भी तेजी का दौर जारी है. शुक्रवार, 20 नवंबर को रुपया सात महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया. वहीं सेंसेक्स और निफ्टी ने भी नौ महीने का हाई छू लिया. खास बात ये है कि रुपए में इस महीने आई मजबूती पिछले आठ साल में सबसे बेहतर मासिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है.मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 20 नवंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले 92.68 पर बंद हुआ. अक्टूबर के आखिरी कारोबारी दिन यानी 31 अक्टूबर को यह 94.96 प्रति डॉलर पर था. इस तरह नवंबर में अब तक रुपए में करीब 2.46 फीसदी की मजबूती आई है।

टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 700 बनाने में भारत दूसरे नंबर पर

पांचवें वनडे में गेंदबाजों ने दिलाई करिश्माई जीत

न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय टीम ने पहली पारी 720 रन बनाकर घोषित कर दी. टीम इंडिया के लिए केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शतक लगाया और कप्तान शुभमन गिल सहित चार बल्लेबाजों ने फिफ्टी लगाई. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. आजकल टेस्ट मैचों में 600-700 जैसे बड़े स्कोर कम ही देखने को मिलते हैं. मगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के इस दौर में एक टीम टिक जाए तो शायद 1000 रन भी कम पड़ जाएं. हालांकि अब तक टेस्ट के इतिहास में कभी एक पारी में 1000 रन नहीं बने हैं. यहां आप उन टीमों की लिस्ट देख सकते हैं, जिन्होंने टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 700 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं.



भारत ने पांचवीं बार 700 का आंकड़ा छुआ

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने 720 रन बनाए. यह कुल पांचवीं बार है जब भारत ने रेड-बॉल क्रिकेट में 700 रनों का आंकड़ा छुआ है. मगर टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 700+ रन बनाने वाली टीमों में भारत दूसरे स्थान पर है. जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज इस सूची में भारत से पीछे हैं, जिन्होंने चार-चार बार यह मुकाम हासिल किया है.

टेस्ट में सबसे ज्यादा 700+ रन

7 बार - श्रीलंका
5 बार - भारत
4 बार - ऑस्ट्रेलिया
4 बार - इंग्लैंड
4 बार - वेस्टइंडीज
2 बार - पाकिस्तान

श्रीलंका ने सबसे ज्यादा 7 बार रेड बॉल क्रिकेट में 700 रनों का आंकड़ा पार किया है. टीम इंडिया इस लिस्ट में उसके पीछे-पीछे चल रही है, जिसने पांच बार 700+ स्कोर बनाया है. पाकिस्तान केवल दो बार ऐसा कर पाया है. श्रीलंका और इंग्लैंड ऐसे 2 देश हैं, जिन्होंने एक टेस्ट पारी में 900 रनों का आंकड़ा छुआ है. टेस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर पिछले 29 सालों से श्रीलंका के नाम है. साल 1997 में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 952 रन बना डाले थे. ये वही मैच था जिसमें सनथ जयसूर्या ने 340 रन बनाए थे.



टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के, ऋषभ पंत बने वर्ल्ड नंबर-2

नई दिल्ली। ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 128 रनों की शतकीय पारी खेली. इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में कुल 16 बाउंड्री लगाईं, जिनमें 6 छक्के भी शामिल रहे. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की लिस्ट में ब्रेंडन मैककुलम को पीछे छोड़ दिया है. पंत अब अपने करियर में 108 छक्के लगा चुके हैं. टीम इंडिया की पारी के 147वें ओवर में ऋषभ पंत ने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर छक्का लगाकर अपना नौवां टेस्ट शतक पूरा किया था. उन्होंने जो बड़ा हिट लगाया, वह उनके टेस्ट करियर का 108वां छक्का भी रहा, जिससे उन्होंने ब्रेंडन मैककुलम को पीछे छोड़ दिया है. पंत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बराबरी भी कर ली है.

टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में ऋषभ पंत दूसरे स्थान पर आ गए हैं. उन्होंने ब्रेंडन मैक्कुलम को पीछे छोड़ा, जिन्होंने टेस्ट में 107 छक्के लगाए थे, जबकि पंत के नाम 108 सिक्स हैं. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के नाम है, जिन्होंने अपने करियर में 138 सिक्स लगाए थे.

T20 डेब्यू में जमशेद आलम ने रचा इतिहास, लिए 4 लगातार विकेट

नई दिल्ली। जमशेद आलम ने टी20 में ड्रीम डेब्यू किया है, उन्होंने अपने पहले ही मैच में 4 लगातार विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. ये उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रेलवे के लिए डेब्यू करते हुए सौराष्ट्र टीम के खिलाफ किया. 23 वर्षीय गेंदबाज उत्तर प्रदेश टी20 लीग में मेरठ मावेरिक्स टीम का हिस्सा रहे हैं. रविवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रेलवे बनाम सौराष्ट्र मैच इंदौर के डेली कॉलेज ग्राउंड पर खेला गया. ये जमशेद आलम का टी20 डेब्यू मैच था, जिसमें उन्होंने लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए. सौराष्ट्र की शुरुआत ही खबर हुई थी, पहले ओवर की दूसरी गेंद पर विश्वराज जडेजा शून्य पर आउट हो गए थे. इसके बाद आलम ने चौथे ओवर में हैट्रिक ली.जमशेद ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर हार्विक देसाई को कैच आउट कराया. अगली गेंद पर उन्होंने प्रेरक मांकड़ को बोल्ड किया. पांचवीं गेंद पर रुचित अहिर को आउट कर उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की. इसके बाद आए समर गज्जर भी खाता नहीं खोल पाए और जमशेद का चौथा शिकार बने. जमशेद आलम टी20 फॉर्मेट में लगातार 4 विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. लगातार 4 विकेट लेने के बाद उन्होंने छठे ओवर में सिद्धांत राणा को एलबीडबल्यू आउट किया. 183 रनों का पीछा करते हुए हरवंश पंगालिया ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वह सौराष्ट्र को जीत तक नहीं पहुंचा पाए।



IPL 2027 का पूरा सीजन नहीं खेलेंगे पैट कमिंस?

नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद के एक प्लेयर ने उस बात के बारे में बताया जो उनकी पैट कमिंस के साथ हुई. इसमें कमिंस ने IPL 2027 में खेलने को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है. बता दें कि बिजी शेड्यूल और ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड आईपीएल के आगामी सीजन से हट चुके हैं. दोनों को उनकी फ्रेंचाइजियों ने रिलीज कर दिया, लेकिन कमिंस SRH द्वारा रिटेन किए गए हैं. इससे उनके खेलने की उम्मीद अधिक है, इस बीच एक नया अपडेट आया है. पैट कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं. फ्रेंचाइजी का उन्हें रिलीज न करना इस बात का संकेत है कि वह IPL 2027 में खेलेंगे. रिपोर्ट के अनुसार अब कमिंस ने भी पुष्टि कर दी है कि वह खेलेंगे, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि वह कुछ मैचों में ही खेलते हुए नजर आ सकते हैं.



टीम के एक सीनियर प्लेयर ने क्रिकबज को उस बातचीत के बारे में बताया जो उनकी पैट कमिंस के साथ हुई. उन्होंने बताया, "मेरी कमिंस से बात हुई, उन्होंने कहा है कि वह आईपीएल खेलने भारत जरूर आएंगे. अगर पूरे सीजन के लिए नहीं तो कुछ मैचों के लिए जरूर आएंगे."बता दें कि पैट कमिंस आईपीएल के पिछले संस्करण में भी कुछ मैचों में नहीं खेले थे. तब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें खेलने की अनुमति नहीं दी थी.

19 साल के Youtuber का खाता फ्रीज, SBI भरेगा 15000 का जुर्माना

नई दिल्ली। अगर आप YouTube से कमाई करते हैं और आपका बैंक खाता भी उसी कमाई के लिए इस्तेमाल होता है, तो यह खबर आपके लिए अहम है. राजस्थान के जोधपुर में ऑनलाइन कमाई करने वाले एक 19 साल के YouTuber को बैंक की कारवाई के कारण परेशानी झेलनी पड़ी. उसने अपने YouTube चैनल को प्रमोट करने के लिए गूगल पर 1,000 रुपये के तीन ट्रांज़ैक्शन किए थे. इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने उसका सेविंग्स अकाउंट फ्रीज कर दिया था. बाद में यह मामला जोधपुर के जिला कंज्यूमर कमीशन पहुंचा, जहां बैंक यह साबित नहीं कर पाया कि खाते से हुए लेनदेन गैरकानूनी थे. इसके बाद आयोग ने SBI बैंक को खाता अनफ्रीज करने और कुल 15,000 रुपए देने का आदेश दिया. यह मामला राजस्थान के जोधपुर के नेवरा गांव के रहने वाले अर्जुन का है. उसने अपने YouTube चैनल से होने वाली कमाई प्राप्त करने के लिए SBI की नेवरा रोड शाखा में सेविंग्स अकाउंट खुलवाया था. आरोप है कि 19 मई 2023 को उसने Google के जरिए 1,000 रुपए के तीन लेनदेन किए थे. बैंक ने इन ट्रांजैक्शन को संदिग्ध मानते हुए बाद में उसका खाता फ्रीज कर दिया. इससे अर्जुन अपने खाते में जमा पैसे नहीं निकाल पा रहा था. बैंक का कहना था कि अर्जुन ने छात्र के रूप में खाता खुलवाया था।

सोने-चांदी में भारी गिरावट, लोगों का कितना पैसा डूबा?

नई दिल्ली। सोने और चांदी में निवेश करने वालों के लिए बीते कुछ महीने काफी उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. साल 2026 के शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद इन दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में अब बड़ी गिरावट सामने आ रही है. हालांकि, इसका सीधा असर उन लोगों की जमा पूंजी पर पड़ा है, जिन्होंने ऊंचे भाव पर सोना या चांदी खरीदी थी. 20 नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी के उच्चतम स्तर से सोना करीब 31.5% और चांदी 64.2% तक टूट चुकी है. ऐसे में अगर किसी ने जनवरी में इनमें 10 लाख रुपए लगाए हो, तो अब उसके निवेश की कीमत काफी कम रह गई है.



10 लाख रुपए लगाने वालों को कितना नुकसान?

अगर किसी ने जनवरी में सोने में 10 लाख रुपए लगाए हो, तो 20 नवंबर तक उसकी कीमत घटकर करीब 6.85 लाख रुपए होगी. यानी उसे 3.15 लाख रुपए का नुकसान होगा. वहीं, चांदी में 10 लाख रुपए लगाने वाले निवेशक की रकम घटकर सिर्फ 3.58 लाख रुपए रह जाएगी. इस तरह चांदी में करीब 6.42 लाख रुपए की गिरावट दर्ज है.

कीमतों में गिरावट की वजह क्या है?

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना जनवरी में करीब 5,600 डॉलर (लगभग 5.02 लाख रुपए) प्रति औंस तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में 4,000 डॉलर (करीब 3.59 लाख रुपए) से नीचे आ गया. वहीं, चांदी भी 100 डॉलर (करीब 8,970 रुपए) प्रति औंस पार करने के बाद अचानक फिसल गई. इसके बाद डॉलर की मजबूती, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदें, महंगाई और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने कीमतों पर दबाव बनाया है.

क्या आगे फिर बढ़ेंगे सोने के दाम?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नवनीत दमानी के मुताबिक, वैश्विक अनिश्चितता के बीच सोने की अहमियत बनी हुई है, लेकिन इसकी कीमतें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों, डॉलर और महंगाई से प्रभावित होती रहेंगी. वहीं, कुछ बाजार एक्सपर्ट मौजूदा गिरावट को खरीदारी का मौका मान रहे हैं।

IEA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगेंगे 20 करोड़ नए एसी

2035 तक हर घर में होगा एयर कंडीशनर

नई दिल्ली। भारत में गर्मी बढ़ने के साथ आने वाले सालों में एयर कंडीशनर (AC) की मांग भी तेजी से बढ़ सकती है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 10 साल में भारत के घरों में करीब 20 करोड़ नए AC लगाए जा सकते हैं. इससे देश में बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ेगी और भारत दुनिया में ऊर्जा की बढ़ती मांग का एक बड़ा कारण बनेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया की हिस्सेदारी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले AC की कुल संख्या में बढ़कर 2035 तक 20% हो सकती है. फिलहाल यह 10% से भी कम है. भारत और इंडोनेशिया में पांच में से एक से भी कम घरों में AC है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में करीब 90% घरों में कम से कम एक AC मौजूद है.



भारत में तेजी से बढ़ेगी बिजली की मांग

IEA का अनुमान के मुताबिक, मौजूदा नीतियों के आधार पर भारत में बिजली की मांग अगले 10 साल तक हर साल करीब 6% बढ़ सकती है. यह किसी भी बड़े क्षेत्र के मुकाबले सबसे तेज वृद्धि होगी. वहीं, देश की कुल ऊर्जा की मांग सालाना 2.5% बढ़ने की उम्मीद है.

गर्मी बढ़ी तो क्या बिजली की खपत और बढ़ेगी?

रिपोर्ट में लंबे और ज्यादा गर्मी वाले मौसम का असर भी बताया गया है. ऐसे हालात में AC की खरीद और इस्तेमाल दोनों बढ़ सकते हैं. ऐसे में कूलिंग के लिए बिजली की मांग सामान्य अनुमान से करीब 40% यानी 700 टेरावॉट-घंटे ज्यादा हो सकती है. इससे बिजली की सबसे ज्यादा मांग वाले समय यानी पीक डिमांड पर दबाव बढ़ेगा.

2035 तक बढ़ेगा बिजली उत्पादन

भारत ने 2025 में करीब 2,114 टेरावॉट-घंटे बिजली का उत्पादन किया था. IEA के अनुमान के मुताबिक, 2035 तक यह बढ़कर 3,585 टेरावॉट-घंटे हो सकता है. इसमें 51% बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आने की उम्मीद है. हालांकि, बिजली उत्पादन में कोयले की भूमिका भी अहम रहेगी.

AC के अलावा भी बढ़ेगी ऊर्जा की जरूरत

AC के अलावा देश में वाहनों की संख्या, इमारतों के निर्माण और स्टील-सीमेंट उत्पादन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2035 तक भारत में ऊर्जा क्षेत्र का निवेश 2025 के मुकाबले 85% बढ़ सकता है. यानी इससे ऊर्जा की मांग के साथ बिजली उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत भी सामने आएगी.

रेल की तरह अब मेट्रो से भी होगी सामान की डिलीवरी

नई दिल्ली। शहरों में सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अब मेट्रो रेल का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. GST नेटवर्क (GSTN) ने ई-वे बिल सिस्टम में ट्रांसपोर्ट के नए ऑप्शन के रूप में मेट्रो रेल को शामिल किया है. खासकर बड़े शहरों में माल की ढुलाई के लिए यह सुविधा काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है. GSTN ने 20 नवंबर को जारी एडवाइजरी में बताया कि मेट्रो रेल का ऑप्शन ई-वे बिल बनाने और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जानकारी अपडेट करने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. यह सुविधा फिलहाल API यूजर्स के लिए टेस्टिंग यानी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में भी शुरू की गई है. हालांकि, लाइव सिस्टम में इसे लागू करने की तारीख अलग से बताई जाएगी.मेट्रो रेल को शामिल किए जाने के बाद ई-वे बिल सिस्टम में सामान पहुंचाने के कुल पांच तरीके हो गए हैं. इनमें सड़क, रेल, हवाई जहाज, जहाज और मेट्रो रेल शामिल हैं. ऐसे में मेट्रो से सामान भेजने वाले कारोबारियों को ई-वे बिल बनाते समय ट्रांसपोर्ट का यह ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद ही संबंधित ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर दर्ज करना होगा.GSTN के मुताबिक, मेट्रो रेल का ऑप्शन ई-वे बिल में ट्रांसपोर्ट की जानकारी बदलने, वाहन से जुड़ी जानकारी अपडेट करने और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाने या दोबारा तैयार करने में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।



धरसींवा को 27.53 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर जिले के धरसींवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चरौदा में आयोजित कार्यक्रम में 27 करोड़ 53 लाख 87 हजार रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगात दी। इन कार्यों से क्षेत्र में सिंचाई, सड़क, विद्युत और ग्रामीण अधोसंरचना सुविधाओं का विस्तार होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शेड निर्माण एवं पेवर ब्लॉक कार्य तथा ग्राम चरौदा में नवीन मंगल भवन निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने विधायक श्री अनुज शर्मा के नेतृत्व में धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के सभी 144 गांवों तक पहुंचने वाली सेवा संवाद यात्रा का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद श्री रणविजय सिंह जूदेव सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांवों का विकास और किसानों की समृद्धि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आज धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में 27 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी, ग्रामीण सड़कों का विस्तार होगा तथा बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी।

दंतेवाड़ा में बनेगी जनजातीय गौरव वाटिका

शहर सत्ता/रायपुर। जनजातीय समाज के महानायकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की गाथाओं से नई पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा जिले में जनजातीय गौरव वाटिका विकसित की जाएगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर स्थित मेंडका डोबरा मैदान में आयोजित जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, जिससे नई पीढ़ी तक वीरों की गाथाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने देश की आजादी और संस्कृति की रक्षा के लिए हुए संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि 17 नवंबर 1913 को राजस्थान-गुजरात सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुए भील जनजातीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सेना ने एकत्रित आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसे मानगढ़ नरसंहार या आदिवासी जलियांवाला बाग कहा जाता है। इस घटना में लगभग 1,500 जनजातीय लोगों के शहीद होने का उल्लेख मिलता है।

अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर कार्रवाई, 1237 क्विंटल धान जब्त

शहर सत्ता/रायपुर। धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं कोचियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने राज्य शासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कांकेर जिले में भी विभिन्न स्थानों पर जांच के दौरान अवैध धान के प्रकरण दर्ज कर धान जब्ती की कार्रवाई की गई है। कांकेर के जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार जिले में कोचियों एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कुल 16 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन कार्रवाईयों में 1237 क्विंटल धान जब्त किया गया है। संबंधित प्रकरणों में मंडी अधिनियम, 1972 के तहत कार्रवाई की गई है। दो मामलों में मंडी अधिनियम की धारा 19 एवं 23 के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान चारामा, पखांजूर, कोयलीबेड़ा, कांकेर, अंतागढ़ एवं दुर्गूकोंदल सहित विभिन्न क्षेत्रों में धान जब्ती की कार्रवाई की गई। इसमें धान व्यापार से जुड़े फर्म संचालकों, कोचियों एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

केंद्रीय जेल रायपुर के 70 बंदियों को मिला कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र

40 पुरुष बंदियों ने सीखी कंप्यूटर की बारीकियां, 30 महिला बंदियों को ब्यूटी पार्लर एवं हेयर ड्रेसिंग का प्रशिक्षण





शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में बंदियों के सुधार, पुनर्वास एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में संचालित 'निश्चय कार्यक्रम' के अंतर्गत शिक्षा और कौशल विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय जेल रायपुर में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में कंप्यूटर शिक्षा एवं ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले 70 बंदियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। यह पहल बंदियों को रिहाई के बाद सम्मानजनक आजीविका के अवसरों से जोड़ने और समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के जन शिक्षण संस्थान निदेशालय तथा जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 40 पुरुष बंदियों को 'कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट' तथा 30 महिला बंदियों को 'असिस्टेंट हेयर ड्रेसर (एडवांस)' के अंतर्गत ब्यूटी पार्लर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

बंदियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन रहा 'निश्चय कार्यक्रम' : जेल महानिदेशक श्री गुप्ता

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ के महानिदेशक श्री हिमांशु गुप्ता ने प्रशिक्षण प्राप्त बंदियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि जेलों में बंदियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना सुधारात्मक प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 'निश्चय कार्यक्रम' इसी उद्देश्य को साकार करने की दिशा में सार्थक पहल है। श्री गुप्ता ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों का महत्वपूर्ण आधार बन गई है। कंप्यूटर प्रशिक्षण से बंदियों में डिजिटल साक्षरता, तकनीकी दक्षता और आत्मविश्वास का विकास होगा। वहीं महिला बंदियों को हेयर ड्रेसिंग एवं ब्यूटी पार्लर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने से उन्हें रिहाई के पश्चात स्वरोजगार प्रारंभ करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कौशल विकास केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को विकसित करने का भी सशक्त जरिया है।

शिक्षा और हुनर से मजबूत होगी आत्मनिर्भरता की नींव

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जन शिक्षण संस्थान रायपुर के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री ठाकुर राम सिंह ने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले बंदियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के साथ जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। तकनीकी ज्ञान एवं व्यावसायिक दक्षता के माध्यम से बंदी भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

चक्रवात से प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत

फसल क्षति का सर्वे करने खेतों तक पहुंचा प्रशासन



शहर सत्ता/रायपुर। अकवान चक्रवात के कारण जिले में हुई फसल क्षति से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बेमेतरा जिला प्रशासन ने तत्परता के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशन में राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीमें गांव-गांव पहुंचकर फसलों को हुए नुकसान का विस्तृत सर्वे कर रही हैं। चक्रवात के कारण हुई बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित किसानों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सर्वे कार्य पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान राहत एवं मुआवजे से वंचित न रहे।

अकवान चक्रवात के प्रभाव से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के कारण कटाई के लिए तैयार धान की फसल खेतों में गिर गई, वहीं बारिश के चलते खेतों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई।

इससे किसानों के सामने फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने और उत्पादन में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई है। किसानों की इस परेशानी को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर वास्तविक क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए।

मजगांव, ठेलका और बनोरा में खेत-खेत पहुंचकर किया फसल क्षति का आकलन

कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में शनिवार को राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने तहसील दाढ़ी के ग्राम मजगांव तथा थानखमरिया क्षेत्र के ग्राम ठेलका एवं बनोरा का दौरा किया। अधिकारियों ने प्रभावित किसानों के खेतों में पहुंचकर धान की फसलों की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों से सीधे संवाद कर चक्रवात के कारण हुए नुकसान, फसल की वर्तमान स्थिति तथा खेती से जुड़ी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की गई। संयुक्त सर्वे दल द्वारा खेतों में गिरी धान की फसल, जलभराव से प्रभावित रकबे तथा अन्य प्रकार की क्षति का आकलन किया गया। अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि फसल नुकसान का वास्तविक मूल्यांकन कर शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप राहत दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।

धान खरीदीः किसानों की समस्याओं पर शासन की त्वरित कार्रवाई

शहर सत्ता/रायपुर। धान खरीदी वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों की समस्याओं और शिकायतों पर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ज़िला स्तर तक प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी है। भू-अभिलेख, विपणन और सहकारिता विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी पंजीकृत किसान को धान बेचने में परेशानी न हो। एग्री स्टेक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण से जुड़े रकबा सुधार के मामलों में अब किसानों को तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। समिति मॉड्यूल में 'खसरा मैपिंग' और 'एग्री स्टेक से भूमि विवरण सिंक' का विकल्प दिया गया है। इसके ज़रिए समिति ऑपरेटर छूटे हुए खसरे जोड़ रहे हैं और तहसीलदारों के अनुमोदन के बाद विवरण अपडेट हो रहा है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और पीवी सर्वे के आँकड़ों का प्रकाशन कर आपत्तियों का भौतिक सत्यापन और निराकरण किया जा रहा है। प्रदेश की 12 तहसीलों में ग्राम सभाओं से मिली 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।



32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अंतर्गत राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उत्साहपूर्ण समापन



शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिकों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और नवाचार की प्रतिभा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के संकल्प के साथ 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में उत्साहपूर्ण समापन हुआ। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के सहयोग से 20 एवं 21 नवम्बर को आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए बाल वैज्ञानिकों ने अपनी शोध परियोजनाओं और वैज्ञानिक मॉडलों के माध्यम से प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राज्य स्तरीय आयोजन में कुल 156 शोध परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनका विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 15 विषय विशेषज्ञों ने मूल्यांकन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वरिष्ठ वर्ग के 10 एवं कनिष्ठ वर्ग के 6 सहित कुल 16 बाल वैज्ञानिक समूहों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया।

जिज्ञासा को कभी समाप्त न होने दें - कुलपति श्री शुक्ल

समापन समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल ने बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक बनने के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने आसपास की घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखना, उनके कारणों को समझना और लगातार प्रश्न पूछना भी आवश्यक है। जिज्ञासा ही नवाचार की वास्तविक आधारशिला है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन केवल प्रतियोगिता में प्राप्त स्थान से न करें। सफलता केवल प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। किसी समस्या को नए दृष्टिकोण से समझना, उसका समाधान खोजना और अपने विचारों को विकसित करना ही वैज्ञानिक उपलब्धि की वास्तविक शुरुआत है। उन्होंने दैनिक जीवन के एक अभिनव उदाहरण का उल्लेख करते हुए बताया कि किस प्रकार अनुपयोगी प्लास्टिक पेन एकत्रित करने के लिए विकसित 'पेन बिन' जैसी छोटी पहल भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। उन्होंने कहा कि नवाचार हमारे आसपास मौजूद है, आवश्यकता केवल सजग दृष्टि और रचनात्मक सोच की है।

जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रभावी नियम बनाने पर विशेषज्ञों ने किया मंथन



शहर सत्ता/रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राज्य जैव विविधता नियम, 2026 के प्रारूप पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला कल रायपुर में आयोजित की। इसमें जैव विविधता संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर मंथन हुआ। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के तकनीकी समिति और सदस्य, विभाग में वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद्, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि और जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक शामिल हुए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव श्री अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन और राष्ट्रीय नियामक व्यवस्था में हुए बदलावों के अनुरूप राज्य में प्रभावी नियम बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नए नियम राज्य की जरूरतों के अनुरूप और समावेशी हों, इसके लिए सभी हितधारकों की भागीदारी आवश्यक है। कार्यशाला में प्रस्तावित राज्य जैव विविधता नियम, 2026 के प्रमुख प्रावधानों, संशोधनों और संस्थागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों और हितधारकों ने नियमों के विभिन्न प्रावधानों पर अपने सुझाव रखे। इस दौरान नियमों को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों, आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार के उपायों पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने जैव विविधता प्रबंधन के संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने, जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की कार्यप्रणाली में सुधार और लोक जैव विविधता पंजियों (पीबीआर) के निर्माण एवं अद्यतनीकरण पर जोर दिया। जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनसे मिलने वाले लाभ के संबंध में व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

PDS फर्जीवाड़ा, परमानेंट बेगुनाह, प्लेसमेंट कर्मी दोषी

40 करोड़ के कीड़े वाले चावल पीडीएस में पास

केंद्र की जांच में सनसनीखेज खुलासा

ढाई साल बाद जांच में सिर्फ 9 प्लेसमेंट कर्मी ब्लैकलिस्ट

18 सरकारी गोदामों की जांच की गई थी

118 में से 72 सैंपल (61%) निर्धारित मानकों पर खरे नहीं

शहर सत्ता ने पहले ही किया था खुलासा



मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी गोदामों में गरीबों को बांटने के लिए रखे गए करीब 40 करोड़ रुपए के कीड़े लगे और मिलावटी चावल को क्वालिटी इंस्पेक्टरों ने पास कर दिया। केंद्र सरकार की जांच में इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की केंद्रीय टीम ने 19 मार्च से 4 अप्रैल 2024 के बीच प्रदेश के 18 सरकारी गोदामों की जांच की थी। इसमें 118 में से 72 सैंपल (61%) निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। कई स्टैकों में कीड़े रेंग रहे थे और चावल में घुन के साथ दाल, गेहूं व चने की मिलावट थी। इसके बावजूद इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए स्वीकृत कर दिया गया।

शहर सत्ता ने पहले ही यह खुलासा किया था और पड़ताल में सामने आया है कि इतने बड़े मामले में ढाई साल बाद भी कार्रवाई महज 9 प्लेसमेंट क्वालिटी इंस्पेक्टरों को ब्लैकलिस्ट करने तक सीमित है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 5 कर्मचारी 2026 में सिस्टम का हिस्सा ही नहीं थे। इस मामले में न तो किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और न ही इन्हें नियुक्त करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी 'कॉल मी सर्विसेज' से जवाब मांगा गया है। गोदामों की निगरानी करने वाले नियमित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी अब तक तय नहीं की गई है।

कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति

केंद्रीय जांच रिपोर्ट के बाद राज्य के खाद्य विभाग ने 10 मई 2024 को संयुक्त जांच टीम गठित करने, दोषियों पर कार्रवाई और अमानक चावल बदलवाने के निर्देश दिए थे। लेकिन ढाई साल तक फाइलें दबी रहीं। अब 6 नवंबर 2026 को 9 प्लेसमेंट क्वालिटी इंस्पेक्टरों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जिनमें से केवल 4 ही वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके अलावा, इन निरीक्षकों द्वारा 2024 के बाद पास किए गए अन्य लॉट की जांच भी नहीं कराई गई है। ऐसे में पूरी व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

रिकॉर्ड अधूरे, बोरों पर गुटखा थूकने के निशान

जांच में कई गोदामों में मिलवार भंडारण नहीं मिला, जिससे यह पहचानना मुश्किल हो गया कि किस मिल ने कौन-सा चावल सप्लाई किया है। स्टॉक रजिस्टर, स्टैक कार्ड और नमी जांच के प्रमाणपत्र भी अधूरे या गायब थे।

आधी-अधूरी जांच: फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) का प्रतिशत दर्ज करने के बजाय रिकॉर्ड में सिर्फ 'हां' या 'नहीं' लिखा था। बोरों पर निर्माण तारीख और लॉट नंबर नहीं थे, न ही दानों की टूट-फूट और रंग की जांच की गई थी।

बदइंतजामी : गोदामों की छत से पानी का रिसाव, चूहे-पक्षियों की गंदगी और बोरों पर तंबाकू थूकने के निशान मिले। कई जगह अमानक चावल समय पर नहीं हटाया गया और संबंधितों से भंडारण शुल्क भी नहीं वसूला गया।

72 स्टैक में 1.16 लाख क्विंटल चावल, कीमत 39.66 करोड़

अमानक मिले 72 स्टैकों में करीब 1 लाख 16 हजार 640 क्विंटल चावल होने का अनुमान है। ये मात्रा प्रति स्टैक 1,620 क्विंटल चावल के हिसाब से है। 34 रुपए प्रति किलो की सरकारी खरीदी दर से कीमत करीब 39.66 करोड़ रुपए होती है। इतना खराब चावल मिलने पर भी जिम्मेदार मिलरों, निरीक्षकों, अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

इस बार धान बेचने के लिए टोकन व्यवस्था को डिजिटल किया गया है। किसान तुंहर टोकन ऐप के जरिए घर बैठे धान बेचने का टोकन बुक कर सकेंगे। इसके अलावा समितियों से भी टोकन जारी किए जाएंगे। इससे किसानों को टोकन लेने के लिए बार-बार सोसायटी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

एग्रीस्टैक और डिजिटल सर्वे से होगा फसल का सत्यापन

इस साल धान खरीदी व्यवस्था में एग्रीस्टैक आईडी और डिजिटल क्रॉप सर्वे को भी जोड़ा गया है। इसके तहत पंजीकृत किसानों के खेतों में बोई गई फसल और रकबे का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। धान खरीदी के लिए किसान की पात्रता तय करने में फसल और रकबे का सत्यापन अहम होगा। इसके साथ ही बायोमेट्रिक व्यवस्था से किसान की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।

ब्लैकलिस्ट इंस्पेक्टरों पांच सिस्टम से ही बाहर

वर्तमान में कार्यरत (4 कर्मचारी)	सिस्टम से बाहर हो चुके
▪ हिमांशु दिलीवाड़ (रायपुर)	• मुस्कान कैनवर्ट (सिस्टम में नाम नहीं)
▪ हफीज खान (कांकेर)	• महेंद्र चंद्राकर • देवी चंद्राकर
▪ नेहा चंद्राकर (कोरबा)	• राजेंद्र राठौर • दीपक चंद्रकर
▪ लोकेश चंद्रवंशी (राजनांदगाव)।	(ये चारों वर्तमान में कार्यरत नहीं है)।

"कुछ क्वालिटी इंस्पेक्टरों को ब्लैकलिस्ट किए जाने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। विस्तृत जानकारी के लिए फाइल मंगवाई है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।"
-संजय श्रीवास्तव, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम



गोदामों में रिकॉर्ड अधूरे, बोरों पर गुटखा थूकने के निशान

महासमुंद: मिलवार स्टैकिंग नहीं, चावल में कीट मिले। (4 में से 3 सैंपल फेल)
बसंतपुर: मिलवार भंडारण नहीं, चावल में दाल, गेहूं, कीड़े मिले। (2 में 1 सैंपल फेल)
तिलई: 4 स्टैकों में कीड़े, छत से रिसाव और बोरों पर तंबाकू के निशान। (3 सैंपल फेल)
कोरबा: बोरियों पर अलग-अलग मिलों व लॉट के निशान, रीसाइक्लिंग की आशंका। (पांचों सैंपल फेल)
जगतारा-4 (बालोद): कीटों का प्रकोप, घुन लगे दाने, कीटनाशक का उपयोग नहीं। (9 में से 3 सैंपल फेल)
पांडोनगर (विश्रामपुर): गोदाम के शीशे टूटे, गेट पर जाली नहीं। चावल में गेहूं, चना, कीड़े। (1 सैंपल फेल)
श्यामपुर (सूरजपुर): जाली, शौचालय और मिलवार भंडारण नहीं। वेंटिलेटर टूटे मिले। (8 में 7 सैंपल फेल)
बनेया (सीतापुर): रिकॉर्ड अधूरे। घटिया चावल 20 दिन से पड़ा, भंडारण शुल्क नहीं लिया। (2 सैंपल फेल)
बैकुंठपुर: एफआरके, नमी जांच के प्रमाणपत्र गायब, नियमित निरीक्षण नहीं। (14 में से 11 सैंपल फेल)
बगीचा: एफआरके का प्रतिशत दर्ज नहीं, बिना पूरी जांच के चावल का वर्गीकरण। (6 में से 4 सैंपल फेल)
मनेंद्रगढ़: फोर्टिफाइड, सामान्य चावल मिक्स मिला। गंदगी और बाहरी राज्यों के बोरे मिले। (9 में 3 सैंपल फेल)
राजपुर: बोरों पर लॉट नंबर नहीं, पुराने रिकॉर्ड गायब। मंजूरी से पहले भंडारण। (5 में से 3 सैंपल फेल)
खरसिया: एक ही लॉट का चावल दो स्टैकों में। कीड़े, रिसाव, तंबाकू के निशान। (10 में से 5 सैंपल फेल)
किरोड़ीमल नगर (रायगढ़): उतराई रजिस्टर में तारीख व स्टैक नंबर नहीं। मौके पर स्टॉक अधिक मिला।
बोडासागर: मंजूरी से पहले भंडारण। एफआरके प्रतिशत, दानों की गुणवत्ता नहीं जांची। (5 में से 2 सैंपल फेल)
बाराद्वार: मंजूरी से पहले माल रखा गया। बोरियों पर लॉट नंबर व तारीख नहीं। (2 में से 1 सैंपल फेल)
गुल्लीदांड (मरवाही): रजिस्टर अधूरे। अमानक चावल नहीं हटा, भंडारण शुल्क नहीं वसूला। (1 सैंपल फेल)
पेंड्रा रोड: मिलवार भंडारण नहीं। एफआरके बैच, नमी जांच के प्रमाणपत्र गायब। (12 में से 5 सैंपल फेल)



बाहरी राज्यों के बोरे मिले, रीसाइक्लिंग की आशंका

जांच रिपोर्ट के बाद राज्य के खाद्य विभाग ने 10 मई 2024 को संयुक्त जांच टीम बनाने, दोषियों पर कार्रवाई, अमानक चावल बदलवाने के निर्देश थे। लेकिन ढाई साल तक फाइलें दबी रहीं। जांच में सामने आया कि जिन इंस्पेक्टरों के पास चावल की गुणवत्ता जांचकर लॉट पास या फेल करने का जिम्मा था, वे विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं बल्कि प्लेसमेंट कर्मी थे। केंद्रीय टीम को गोदामों में बाहरी राज्यों के पुराने बोरे, दोहरी छपाई और अलग लॉट के निशान मिले, जिससे चावल की रीसाइक्लिंग की आशंका है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27